https://swadeshbhartnews

R.N.I. No. UPHIN/2021/82888

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

स्वदेश भारत न्यूज

जौनपुर से प्रकाशित

जौनपुर

मंगलवार 12 मई 2026

वर्ष : 05 - अंक : 19

पृष्ठ - 4 मूल्य - 5:00 रुपये

न्यूज कैप्सूल

नेपाल के दार्चुला मे भूकंप के झटके, घरों से बाहर भागे लोग

काठमांडू। नेपाल के पर्वतीय जिले दार्चुला में रविवार को 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार, यह भूकंप पूर्वाह्न 11 बजकर 55 मिनट पर आया जिसका केंद्र दार्चुला जिले के तपोवन में था। भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई। हालांकि झटके मध्यम स्तर के थे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान, इमारत गिरने या भूस्खलन की सूचना नहीं मिली है। राहत और निगरानी टीमें क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं। दार्चुला जिला भारत के उत्तराखण्ड से सटा हुआ है और यह इलाका भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। हिमालयी क्षेत्र भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार टकराव के कारण अक्सर भूकंप की गतिविधियों का केंद्र बना रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। वर्ष 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई थी और भारी तबाही हुई थी। इसी कारण नेपाल में छोटे भूकंपों को भी गंभीरता से लिया जाता है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है।

भीषण आत्मघाती हमले से दहला पाकिस्तानः 1500 किलो विस्फोटक से उड़ाया बन्नू पुलिस कैंप

कराची। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में शनिवार रात हुए भीषण आत्मघाती हमले ने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया। पुलिस प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में कम से कम 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार हमला रात करीब 8.55 बजे हुआ। हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को पुलिस ठिकाने से टकरा दिया। इसके बाद क्वाडकॉप्टर ड्रोन गतिविधियां देखी गईं और फिर आतंकियों ने जमीनी हमला भी किया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, हमले में लगभग 1,200 से 1,500 किलोग्राम विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। धमाके के बाद राहत और बचाव दल भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटे रहे, क्योंकि आशंका है कि अभी भी कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। आतंकी संगठन 'इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान के अफगानिस्तान सीमा से लगे इलाकों में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कुछ महीनों में चंपेजंद के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और पुलिस पर हमलों में तेजी आई है।

सनातन पर वार करने वाले मिट्टी में मिल गए, आक्रांताओं का नामोनिशान नहीं बचा : सीएम योगी

बागपत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सनातन की आस्था को तोड़ने का प्रयास करने वाले विदेशी आक्रांता इतिहास से मिट गए। उन्होंने कहा कि मंदिरों, मठों और तीर्थ स्थलों को नष्ट करने का प्रयास करने वाले लोग खुद मिट्टी में मिल गए, जबकि सनातन की परंपरा और आस्था आज भी पहले से अधिक मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में केवल भारत ऐसा देश है जिसने सदियों तक विदेशी आक्रांताओं का सामना किया और हर परिस्थिति में अपनी संस्कृति और आस्था की रक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन आक्रांताओं ने सनातन के प्रतीक मंदिरों और तीर्थ स्थलों को विखंडित करने का प्रयास किया था, वही तीर्थ स्थल आज फिर से पुनर्प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, जबकि आक्रांताओं का नामोनिशान तक इतिहास में नहीं बचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागपत की धरती पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि महाभारत काल में भगवान श्रीकृष्ण ने कौरवों से पांडवों के लिए जो पांच गांव मांगे थे,

उनमें बागपत भी शामिल था। आज वही बागपत एक जनपद के रूप में देश और प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना चुका है।उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले जब वह यहां आए थे तब यह स्थान छोटा था, लेकिन स्थानीय लोगों और संतों के प्रयास से इसे भव्य तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए क्षेत्र के लोगों और संतों का आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत में किसानों के मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंह का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था। उनकी कर्मभूमि के कारण बागपत ने देश और दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि इस धरती से कई महान व्यक्तित्व निकले हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की विरासत और विकास दोनों साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बागपत सहित पूरे प्रदेश में विकास और विरासत दोनों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

यहां पर आकर धन्य महसूस कर रहा हूं', पीएम मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में लिया भाग

गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में आयोजित 'सोमनाथ अमृत महोत्सव' में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यहां पर आकर धन्य महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जय सोमनाथ! यहां आकर धन्य महसूस कर रहा हूं! हम इस पुनर्निर्मित मंदिर के भक्तों के लिए अपने द्वार खोलने के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर पावनधाम सोमनाथ आकर दिव्य अनुभूति हुई है। इस अवसर पर मंदिर मार्ग पर भगवान सोमनाथ के भक्तों के जोश और प्रचंड उत्साह को देखकर मन अभिभूत और भावविभोर है! मैं आज यहां उस क्षण को जी रहा हूं, जिसका अनुभव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पुनर्निर्मित मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर किया होगा। सोमनाथ अमृत महोत्सव का भक्तिमय वातावरण हर तरफ अद्भुत ऊर्जा का संचार कर रहा है।पीएम ने लिखा कि सोमनाथ में, हर कोने में भक्ति का अनुभव किया जा सकता है। पुनर्निर्मित मंदिर के भक्तों के लिए अपने द्वार खोलने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अनगिनत लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। वह दिन वास्तव में भारत की सभ्यतागत

यात्रा में एक मील का पत्थर था।वहीं, भारतीय वायु सेना की 'सूर्य किरण' एरोबेटिक्स टीम ने बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर में आयोजित 'सोमनाथ अमृत महोत्सव' के दौरान हवाई करतब दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में एक 'विशेष महापूजा' में भी हिस्सा लिया। बता दें कि ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में आयोजित समारोहों में मंदिर के जीर्णोद्धार और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1951 में इसके उद्घाटन की स्मृति को याद किया गया। धार्मिक समारोहों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर से सोमनाथ पहुंचने के बाद वहां रोड शो किया। वह रविवार रात गुजरात पहुंचने के बाद जामनगर में रुके थे। रोड शो में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मंदिर के पास स्थित वीर हमीरजी सर्कल तक हेलीपैड से लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर हजारों लोग जमा हो गए। जब उनका काफिला इलाके से गुजरा तो समर्थकों ने झंडे लहराए और नारे लगाए, जबकि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के कलाकारों ने मार्ग में निर्धारित स्थानों पर पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए।

एक्शन में शुभेंदु अधिकारीः बंगाल में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, सीएम ने पहले ही दिन लिया अहम फैसला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नवगठित शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में आने वाले महीनों में पुलिस और प्रशासनिक ढांचे में बड़े स्तर पर फेरबदल होने के संकेत मिल रहे हैं। इसकी झलक सरकार के पहले ही दिन देखने को मिल गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर राज्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय की नौकरशाही संरचना में व्यापक बदलाव किए हैं। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पूर्व केंद्रीय कार्यालय से जुड़े 16 नौकरशाहों को बदल दिया गया है। स्थानांतरित किए गए पूर्व अधिकारियों में सबसे प्रमुख नाम 2014 बैच के आईएएस शांतनु मुखोपाध्याय का है, जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी संघ के शीर्ष नेता व केंद्रीय कार्यालय में तैनात प्रताप नायक का तबादला दार्जिलिंग जिले के

बिजनबारी स्थित पालबाजार ब्लॉक विकास कार्यालय में कर दिया गया है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत 46 अधिकारियों को अस्थायी रूप से राज्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में तैनात किया गया है। इन अधिकारियों की अगली तैनाती का निर्णय बाद में लिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों बाद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रता गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं, पश्चिम बंगाल के 2017 बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रता बाला को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का प्रधान सचिव नियुक्त करने की घोषणा की गई है। इससे पहले वे दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट थे।

460 करोड़ के कारोबारी से सत्ता के गलियारों तक, अब दुबई रूट से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का शक

जालंधर। आप सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा लंबे समय तक लुधियाना के प्रमुख उद्योगपति और समाजसेवी के रूप में पहचाने जाते रहे। एससीडी सरकारी कॉलेज से बीकॉम करने के बाद उन्होंने कारोबार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। रितेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हैमटन स्काई रियलिटी जैसे कारोबारी समूहों से जुड़े अरोड़ा पंजाब के सबसे संपन्न नेताओं में गिने जाते हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनकी संपत्ति 460 करोड़ रुपये से अधिक और देनदारियां करीब 37 करोड़ रुपये बताई गई हैं।राजनीति में उनकी एंट्री 2022 में हुई जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 10 अप्रैल 2022 को वे निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। सांसद रहते हुए उन्होंने लुधियाना से जुड़े कई विकास प्रोजेक्टों पर सक्रिय भूमिका निभाई। इनमें हलवारा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और ईएसआई अस्पताल के अपग्रेडेशन जैसे बड़े काम शामिल रहे। 2025 में लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के

बाद हुए इस चुनाव में उन्होंने करीब 10,603 वोटों से जीत दर्ज की।विधानसभा पहुंचने के बाद उन्होंने राज्यसभा सदस्यता छोड़ दी। इसके बाद 3 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें पंजाब कैबिनेट में शामिल किया। उन्हें उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और एनआरआई मामलों जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई।संजीव अरोड़ा की पहचान समाजसेवा से भी जुड़ी रही है। माता-पिता को कैंसर से खोने के बाद उन्होंने 'कृष्ण प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट' की स्थापना की। ट्रस्ट के जरिए 160 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज कराया जा चुका है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक, पूरा मामला फर्जी जीएसटी लेनदेन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संजीव अरोड़ा ने अपनी कारोबारी इकाइयों के माध्यम से दिल्ली स्थित फर्मों से 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन खरीद के फर्जी बिल तैयार करवाए। इन बिलों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का गलत लाभ लिया गया।इसके अलावा निर्यात से जुड़े जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का भी फर्जी तरीके से फायदा उठाया गया। ईडी का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिये सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों को संदेह है कि फर्जी कंपनियों और बोगस फर्मों के जरिये रुपयों की लेयरिंग कर लेनदेन को जटिल बनाया गया ताकि रकम के वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके। ईडी को यह भी शक है कि अपराध से अर्जित धन को निर्यात कारोबार के जरिये विदेश भेजा गया और बाद में दुबई से भारत लाकर उसे वैध दिखाने की कोशिश की गई। अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान कई संदिग्ध बैंकिंग रिकॉर्ड, कारोबारी दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन से जुड़े सबूत मिले हैं। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग और कंपनियां शामिल थीं। ईडी की कार्रवाई जिन पांच स्थानों पर हुई, उनमें चार ठिकाने सीधे तौर पर संजीव अरोड़ा और उनकी कारोबारी इकाइयों से जुड़े बताए जा रहे हैं।

'ईडी सुपारी किलर', आप सांसद संजय सिंह बोले- पूरे देश में चुनावी घोटाले कर रही भाजपा

लखनऊ। आम आदमी पार्टी सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के आंदोलन और जनता के दबाव के कारण सरकार को प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना पर पीछे हटना पड़ा, लेकिन पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के जरिए अभी भी जनता को लूटने का काम जारी है। संजय सिंह ने रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश के गांवों और शहरों में लोग खुद स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंक रहे थे, महिलाओं तक ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। संजय सिंह ने कहा कि किसी का 600 रुपये का बिजली बिल 3000 रुपये आ रहा है, किसी का 2000 रुपये का बिल 10000 रुपये तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि 'मिल्खा सिंह से तेज भागने वाले' स्मार्ट मीटरों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ भी लड़ाई जारी रहेगी। संजय सिंह ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, जिला इकाइयों, प्रांतीय पदाधिकारियों और प्रकोष्ठों को बधाई देते हुए कहा कि उनके संघर्ष और प्रदेश की जनता के दबाव के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और जनता की लूट बंद होने तक आंदोलन जारी रहेगा।संजय सिंह ने शिक्षा व्यवस्था पर कहा कि नीति आयोग और भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 9508 विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या एक शिक्षक के भरोसे मिड डे मील, पढ़ाई और पूरे विद्यालय का संचालन संभव है।

जनता का जीतना है विश्वास, कानून व्यवस्था में होगा सुधारः दिलीप घोष

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब पार्टी जनता का विश्वास जीतने में लगी है। मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि आज छुट्टी है और सोमवार को एक बैठक होगी जिसमें कई निर्णय लिए जा सकते हैं। हम लोग जनता का विश्वास जीत रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी प्राथमिकता बंगाल को एक नए सिरे से फिर से बनाना है क्योंकि कई व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। कानून-व्यवस्था कमजोर है और लोग कई वर्षों से डर के साए में जी रहे हैं। शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल है और उद्योग या रोजगार के अवसर बहुत ही कम हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग पार्टी के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि किसे कौन सी जिम्मेदारियां और भूमिकाएं सौंपी जाएंगी, जिससे पश्चिम बंगाल में विकास

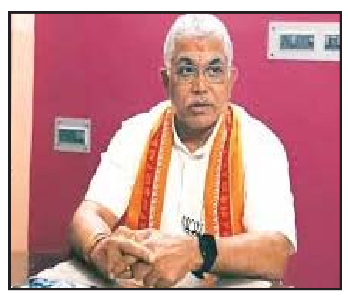

का काम तेजी से हो सके। हमारी प्राथमिकता जनता की समस्याओं को दूर करना है, हम लोग उसी तरह काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में काम करना है। हम तुरंत काम शुरू करेंगे, आपको बदलाव दिखेगा। दिलीप घोष ने कहा कि हमें बंगाल को फिर से बनाना है। यहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं है, लोग डर के साए में जी रहे थे। हमें हर चीज पर काम करना होगा और इसमें समय लगेगा। हालांकि, हम तुरंत काम शुरू कर देंगे और आप बदलाव देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया, जिसे सिर्फ 80 सीटें ही मिल पाईं। जनता को पहले ही विश्वास हो गया था कि भाजपा भी पश्चिम बंगाल का विकास कर सकती है। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, पश्चिम बंगाल का विकास भाजपा की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की जनता से विकास का जो वादा किया है, हम निश्चित तौर पर उसे निभाएंगे। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से घुसपैठ होती थी। भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था मजबूत हो। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम होना चाहिए।

बॉलीवुड ही नहीं, साउथ सिनेमा भी खिंचा चला आएगा कश्मीर, लोकेल टैलेंट से चमकेगी फिल्म इंडस्ट्री

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य को अंतरराष्ट्रीय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए कई नई पहल की घोषणा की है। उनका कहना है कि सरकार स्थानीय संसाधनों और प्रशिक्षित युवाओं के जरिए फिल्म उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मुंबई के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ के साथ मिलकर स्थानीय युवाओं को सिनेमैटोग्राफी, लाइटिंग और अन्य तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दे रही है, ताकि फिल्म यूनिट्स को बाहर से ज्यादा स्टाफ लाने की जरूरत न पड़े। इससे न केवल लागत कम होगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एक 'सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम' लागू कर रही है, जिससे फिल्म शूटिंग की अनुमति आसानी से मिल सके और प्रशासनिक बाधाएं खत्म हों। पर्यटन विभाग के जरिए सभी अनुमतियों को समन्वित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार कैमरा, लाइटिंग और अन्य उपकरणों का स्थानीय स्टॉक भी विकसित करने की योजना बना रही है, ताकि फिल्म यूनिट्स को भारी सामान बाहर से न लाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से जम्मू-कश्मीर न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दक्षिण भारतीय सिनेमा और म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शंस के लिए भी एक पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन सकेगा और इससे घाटी की फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान मिलेगी।

'साहस और शक्ति की विरासत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत' : पीएम मोदी

बंगलूरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बंगलूरू में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज बंगलूरू की धरती से भगवा सूरज उग आया है। एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर, मैं समझता हूं कि जब हजारों भाजपा कार्यकर्ता इतनी सुबह एक साथ आ सकते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। मैं आप सभी का आभारी हूं। बंगाल की जीत आपकी भी जीत है। पीएम मोदी ने कहा, 'आज 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया।' उन्होंने कहा कि साहस और शक्ति की विरासत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी भावना से प्रेरित होकर, तीन दिन पहले हमने 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ मनाई। कल सुबह, 11 तारीख को, मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा, जहां मंदिर के पुनर्निर्माण का उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने

संबोधन में कहा कि आज मैं ऐसे समय में बंगलूरू आया हूं, जब देश में चुनाव परिणामों पर चर्चा चल रही है। पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए की सरकार बनना, असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना, बंगाल में पहली बार भाजपा को इतना बड़ा आशीर्वाद मिलना और अभी-अभी 2 सप्ताह पहले गुजरात के पंचायत और निकाय चुनाव में इतनी भारी विजय मिली कि गुजरात भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये चुनाव परिणाम भारत की राजनीतिक दशा-दिशा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये भारत के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग, हर वर्ग का मूड दर्शाते हैं। इन परिणामों का एक बहुत बड़ा संदेश ये भी है कि अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए। हमें स्कैम नहीं समाधान चाहिए। हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। आज पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आपको याद होगा कि सिर्फ 10 साल पहले बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। लेकिन आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भाजपा की सरकार है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए पर पहुंच गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं, जब केरलम में भी भाजपा-एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम 12 साल से केंद्र में हैं, देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में भाजपा-एनडीए की सरकारें हैं। हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन, दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, जिस पार्टी को 40 साल पहले 400 से अधिक सीट मिली थी। वो पिछले 3 इलेक्शन में सबकुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन, कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रक्रियाएं, कोर्ट के प्रति भी घृणा, मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी मुख्यधारा की पार्टी को ऐसा करते हुए नहीं देखा। वो इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि गाली-गलौच और भद्दी भाषा के सिवाय उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकारों के लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है। हमारा मंत्र सबका साथ-सबका विकास है। हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है। इसलिए हर राज्य में जनता भाजपा को दूसरी-तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है। लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है।

मातृ दिवस पर सीएम रेखा का तोहफाः अनाथ युवाओं के लिए आफ्टरकेयर स्कीम को मंजूरी, 18 के बाद भी सरकार रखेगी ख्याल

नई दिल्ली। चाइल्ड केयर संस्थानों से 18 साल की उम्र के बाद बाहर आने वाले अनाथ और जरूरतमंद युवाओं की देखभाल के लिए दिल्ली सरकार ने 'आफ्टरकेयर स्कीम' को मंजूरी दे दी है। सरकार की इसके जरिए ऐसे युवाओं को पढ़ाई, नौकरी और आर्थिक मदद देकर आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। मातृ दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन युवाओं को स्नेह भरा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को संस्थागत देखभाल छोड़ने वाले युवाओं के लिए आफ्टरकेयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स की घोषणा की। इस योजना का मकसद उन युवाओं को सहारा देना है, जो 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर निकलते हैं और जीवन की नई चुनौतियों का सामना करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल बच्चों को संरक्षण देना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा भविष्य देना है, जहां वे खुद को सुरक्षित और सक्षम महसूस करें। उन्होंने कहा, कोई भी बच्चा बालिग होने के बाद खुद को अकेला न समझे, सरकार उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इस योजना के लिए

वित्त वर्ष 2026-27 में 3.5 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इसके तहत जरूरत के हिसाब से युवाओं की पहचान की जाएगी और उनके लिए अलग-अलग प्लान तैयार किए जाएंगे, ताकि उन्हें सही समय पर सही मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने मातृ दिवस पर लाजपत नगर स्थित विलेज कॉटेज होम का दौरा भी किया और बच्चों से मुलाकात की। यहां उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनका हाल जाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। दिल्ली में इस समय 88 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (सीसीआई) चल रहे हैं, जिन्हें सरकार और गैर-सरकारी संस्थाएं मिलकर संचालित करती हैं। इन संस्थानों में 18 साल तक के बच्चों को रहने, पढ़ाई, सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा दो आफ्टरकेयर होम भी हैं। एक लड़कों और एक लड़कियों के लिए है, जहां 18 साल से ऊपर के युवाओं को सीमित समय के लिए सहारा दिया जाता है। सरकार के मिताबिक हर साल करीब 150 से 200 युवा 18 साल की उम्र के बाद इन संस्थानों से बाहर आते हैं। संस्थान के अंदर उन्हें काफी मदद मिलती है, लेकिन बाहर निकलने के बाद पढ़ाई जारी रखना, नौकरी ढूंढना, रहने की व्यवस्था करना और आर्थिक समस्याओं से जूझना उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बार उन्हें परिवार का सहारा भी नहीं मिल पाता।

2 स्वदेश भारत न्यूज
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र
https://swadeshbhartnews
जौनपुर, मंगलवार 12 मई 2026

सम्पादकीय

तमिलनाडु में विजय

बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब प्रतीक्षा है अप्रत्याशित चुनाव परिणाम वाले दूसरे राज्य तमिलनाडु में सरकार गठन की। चूंकि टीवीके नेता जोसेफ विजय ने डीएमके से छिटकने वाली कांग्रेस, माकपा, भाकपा, वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सहयोग से समर्थन जुटा लिया है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में संदेह नहीं। विजय का अभिनेता से नेता बनकर एक तरह से आनन-फानन मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्होंने दो वर्ष पूर्व अपने दल का गठन किया और पहले ही प्रयास में सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। उनकी जीत यह बताती है कि तमिलनाडु में फिल्म कलाकारों के प्रति लोगों की एक अलग तरह की दीवानगी रहती है। इसी के चलते करुणानिधि और एमजीआर से लेकर जयललिता जैसी फिल्मी हस्तियों ने राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। फिलहाल यह कहना कठिन है कि विजय मुख्यमंत्री के रूप में कैसी राजनीतिक छाप छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें प्रशासन चलाने का कोई अनुभव नहीं। उनकी सरकार पांच दलों के सहयोग पर टिकी होगी, इसलिए एक अभिनेता के रूप में तमाम लोकप्रियता के बाद भी उनके लिए शासन चलाना बहुत आसान नहीं होगा। यह ठीक है कि तमिलनाडु अपेक्षाकृत एक समृद्ध राज्य है, लेकिन विजय ने जिस तरह थोक के भाव लोक-लुभावन वादे कर रखे हैं, उसे देखते हुए उनके लिए उन्हें पूरा करना आसान नहीं होगा।आखिर आर्थिक दृष्टि से सक्षम तमिलनाडु में नेताओं को इतने अधिक लोक-लुभावन वादे क्यों करने पड़ते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में यही अधिक दिखता है कि राज्य का एक तबका अभी भी निर्धनता की परिधि में ही बना हुआ है। यह एक विसंगति ही है। इसमें संदेह है कि रेवड़ियां बांटकर निर्धनता को दूर किया जा सकता है। विजय के मामले में यह भी देखना होगा कि वे द्रविड़ दलों की तरह से ही अपनी राजनीति चलाते हैं या फिर कोई नई राह पकड़ते हैं? द्रविड़ पार्टियों के बारे में यह किसी से छिपा नहीं कि वे हिंदी विरोध के साथ दिल्ली यानी केंद्रीय सत्ता से टकराव मोल लेने की राजनीति करती रही हैं और तमिल अस्मिता के नाम पर तमिलवाद को इस तरह उभारने की भी कोशिश करती रहीं, जैसे यह राज्य शेष देश से विशिष्ट हो। इस तमिलवाद में क्षत्रीय संकीर्णता के साथ प्रायः एक तरह के अलगाववाद की भी बू आती रही है। फिलहाल यह जानना कठिन है कि ईसाइयत को मानने वाले जोसेफ और उनके राजनीतिक दल की विचारधारा क्या है? क्या यह अजीब नहीं कि वे भाजपा को तो धार्मिक पार्टी मानते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग को नहीं? वास्तव में विजय को लेकर एक नहीं कई सवाल हैं। इनमें से एक यह भी है कि कहीं उनके सत्ता में आने से ईसाई मिशनरियों का मतांतरण अभियान और तेज तो नहीं हो जाएगा?

पश्चिम बंगालः परिवर्तन के साथ पुनर्जागरण

राजनाथ सिंह

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की यह पंक्तियाँ केवल एक कविता का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि समय-समय पर स्वतः स्फूर्त और नवीन होने वाली बंगाल की आत्मा का आह्वान भी हैं। गुरुदेव भली-भाँति समझते थे कि बंगाल समय के साथ केवल बदलता नहीं है, बल्कि वह बार-बार बेहतर और नए रूप में पल्लवित होता है। गुरुदेव की जयंती पर गायी जाने वाली यह कविता नवजागरण और नवचेतना की प्रतीक है। यह प्रार्थना पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर, नए, उज्ज्वल और रचनात्मक विचारों के स्वागत का आह्वान भी है। यह एक सुखद संयोग है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती से कुछ दिन पहले ही, पश्चिम बंगाल कई दशकों के बाद नवजागरण का साक्षी बना है। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है। लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह चुनाव कभी सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं था। यह चुनाव इस महान भूमि के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक अवसर था–एक ऐसा सभ्यतागत आह्वान, जो चुनावी समीकरणों और गणनाओं से कहीं ऊपर है। आज जब पश्चिम बंगाल की चेतना और गौरव का अरुणोदय हो रहा है, तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बंगाल क्या है और बंगाल की चेतना का पुनर्जागरण किसे कहा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है बंगाल की शताब्दियों पुरानी चेतना को समझना और जानना। बंगाल सामाजिक चेतना का केंद्र रहने से पहले ज्ञान और आध्यात्मिकता की पवित्र भूमि थी। 15वीं शताब्दी में नबद्वीप के गंगा तट पर एक युवा संन्यासी निमाई ने अपने कीर्तन के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। उस युवा संन्यासी को आज हम आदि संत चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिखाया गया भक्ति मार्ग आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के साथ-साथ सामाजिक समरसता का अभियान भी था। चैतन्य महाप्रभु ने जात-पात और ऊंच-नीच के बंधनों

हे नूतन, देखा दिक आर-बार, जन्मेरो प्रथम शुभोखोन (हे नवीन, एक बार फिर से सामने आओ, ठीक उसी तरह जैसे जन्म के समय वह पहला शुभ क्षण आया था।)

को तोड़ा। उनके द्वारा प्रवाहित वैष्णव परंपरा ने समाज में करुणा, समावेशिता, समता और सद्भावना को बल दिया।यही चेतना बाउल परंपरा में भी दिखाई दी। बाउल परंपरा के फकीरों की पहचान जाति, धर्म या कोई पंथ नहीं, बल्कि मानवता की भावना थी। बाउल परंपरा के सबसे महान प्रवर्तक लालन फकीर थे। वे किस संप्रदाय से थे, यह प्रश्न कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था का भी विरोध किया तथा मुस्लिम समाज में होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठायी। वे बंगाल की उस सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक थे, जिसमें सहिष्णुता और सह-अस्तित्व का भाव समाहित था। विगत तीन शताब्दियों में, बंगाल और बंगाल के लोगों ने केवल भारत के सामाजिक नवजागरण आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, बल्कि उसका नेतृत्व भी किया। जब समाज अपनी जड़ता, कुरीतियों और विकृत परंपराओं के बोझ तले दब चुका था, तब राजा राममोहन राय ने न तो परंपरा का समूल रूप से परित्याग किया और न ही तर्कशून्य तरीके से उसको उचित ठहराया। उन्होंने लोगों को आत्मबोध कराकर, समाज के भीतर से सुधारने का मार्ग चुना। उनका संदेश स्पष्ट था – समाज का पुनर्जन्म बाहर से नहीं, भीतर की चेतना से होता है। सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीति के विरुद्ध उनका संघर्ष केवल समाज सुधार से जुड़ा आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक तप था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मंत्र बना दिया। उन्होंने शिक्षा को नारी शक्ति के उत्थान, सशक्तिकरण और मुक्ति का साधन बना दिया।बंगाल के ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम् जैसा अमर मंत्र राष्ट्र को दिया। वंदे मातरम् वह गीत था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बल दिया और सदियों से सोये हुए देश को जगा दिया। यह गीत आज भी भारत की अंतर-आत्मा का स्वर है। बंगाल ने ही भारत की सबसे पहली महिला चिकित्सक डॉ. कादम्बिनी गांगुली जी को जन्म दिया, जिन्होंने सभी को, विशेषकर महिलाओं को, प्रेरित किया। बंगाल की ही धरती पर जन्मे, प्रखर राष्ट्रवादी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।

संभवतः बंगाल की धरती ने जितनी भी विलक्षण प्रतिभाओं और महान लोगों को जन्म दिया, उनमें सबसे देदीप्यमान और प्रबुद्ध स्वामी विवेकानंद को कहा जा सकता है। शिकागो में दिया गया उनका भाषण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने पूरे विश्व को वेदान्त और भारत के महान सभ्यतागत मूल्यों से परिचित कराया।यह सब बातें बंगाल की आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। यही उसकी सनातन और शाश्वत पहचान रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को इसी दृष्टि से देखते हैं। यह अतीत में लौटने की आकांक्षा नहीं है, न ही यह आधुनिकता की चाह में परायी सभ्यता की प्रतिछाया बनने की लालसा है। यह वह दृष्टि है जो बंगाल को पुनः जागृत करना चाहती है ताकि वह अपने पूर्ण सामर्थ्य के बल पर फिर से अपने सर्वोच्च वैभव को प्राप्त कर सके।दुर्भाग्यवश, लंबे समय तक बंगाल के कुछ बुद्धिजीवियों और राजनीतिक वर्गों ने अपनी ही सांस्कृतिक विरासत को बोझ समझा और उसे हेय दृष्टि से देखा। सभ्यता, धर्म, संस्कृति और बंगाल की चेतना की बात करने वाले लोगों और उनकी आवाज को दबाया गया। परंपरा को पिछड़ापन समझा गया और आधुनिकता के नाम पर औपनिवेशिक मानसिकता को बढ़ावा दिया गया। परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल ने दशकों तक विकासहीनता, अराजकता, संस्थागत पतन और वैचारिक जड़ता का दंश झेला।बंगाल में हुआ यह चुनाव और परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हैं। बल्कि यह ऐसे लोगों के खिलाफ जनादेश भी है जिन्होंने बंगाल को उसके मूल से दूर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पश्चिम बंगाल के गौरव और विरासत को पुनर्स्थापित करने का यज्ञ था।बेलूर मठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मिक जुड़ाव, स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और सुशासन को 'सेवाऽ के रूप में देखने का उनका दृष्टिकोण – ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि 'प्रधान सेवकऽ बंगाल के विकास और पुनर्जागरण को एक पावन दायित्व मानते हैं, जिसे वे अपने 'प्रधान धर्मऽ और 'प्रधान कर्मऽ के रूप में निभा रहे हैं।इसलिए बंगाल के विकास और पुनर्निर्माण का अर्थ कई दशकों से उपेक्षित और जीर्ण-शीर्ण हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो है ही, साथ ही इसका अर्थ उन घाटों को पुनर्जीवित करना भी है जहाँ चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन ने लोगों को भाव-विभोर किया था। इसका अर्थ उन शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त करना भी है जिनका स्वप्न ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने देखा था। इसका अर्थ उन आदिवासी भाइयों-बहनों को गरिमा, सम्मान और अवसर देना भी है जो सदियों से बंगाल में रहते आए हैं। इसका अर्थ लंबे समय से उपेक्षा झेल रहे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना भी है।पिछले कुछ दशकों में भय और कुशासन के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो पश्चिम बंगाल का स्वर्णिम युग बीत चुका हो। किंतु आज बंगाल एक बार फिर नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ समृद्धि एवं शांति से भरे नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के साथ बनने वाली पहली भाजपा सरकार गुरुदेव के द्वारा वर्णित 'नूतनऽ भावना के साथ सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी और बंगाल की प्रतिष्ठा और समृद्धि के साथ बंगाल का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए कार्य करेगी।

लेखक भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं।

मां की ममता का मार्मिक जादू

संगीता मित्तल

10 मई, मदर्स डे। मां को समर्पित एक ही दिन क्यों, हमारे जीवन का हर पल मां की देन है। सभ्यता की शुरुआत से ही मां को हर संस्कृति में पूजा गया। चाहे दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, या धरती माता के रूप में। यहां तो हम अपने देश को भी भारत माता पुकार गौरवान्वित होते हैं। हम दुनिया के शायद ऐसे पहले लोग हैं, जो अपने देश को ही नहीं, बल्कि अपनी बोली से लेकर नदियों, पौधों और गऊ को भी गौ माता कहते हैं। मां सिर्फ जन्म देने वाली हीं नहीं, बल्कि जो पोषण दे, रक्षा करे, ज्ञान दे, समृद्धि दे, उसे भी मां का दर्जा हासिल है। वह हाथ जो माथे पर रखा जाता रू मुझे जब अपनी मां की यादें आती हैं कि कैसे वह घर में सबसे देर में सोती थी और सबसे पहले जगती थी, घड़ी के अलार्म से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके अंदर परिवार का फिक्र था जो उन्हें चौन से नहीं बैठने देता। किस तरह वह बच्चों के कुछ कहने से पहले ही उनके माथे पर हाथ रखकर बुखार टटोल लेती थी। किस तरह परिवार के प्रति उनकी चिंता कभी शोर नहीं करती थी, बस एक धीमी लौ की तरह हमेशा जलती रहती थी, जिसे उन्होंने कभी बुझने नहीं दिया। मैं अब समझती हूं, यही असली जादू है मां का। ये मांएं कुछ अलग हैं रू इस मदर्स डे पर मैं कुछ खास मांओं का जिक्र करना चाहती हूं, जिनके प्रति प्यार किसी ग्रीटिंग कार्ड के जरिए जाहिर नहीं किया जा सकता, ये नारी शक्ति की असल मूर्त हैं, जिन्हें दुनिया ने शायद ही इतने करीब से देखा होगा। कुछ हफ्ते पहले मैं होशियारपुर में 'ऑटिज्म' पीड़ित यानी एक तरह की न्यूरोडिवैल्पमैंटल स्थिति, जो संवाद, सामाजिक व्यवहार और संवेदनाओं को प्रभावित करती है, ऐसे बच्चों के एक स्कूल में गई। मुझे लगा था कि बच्चे भावुक कर देंगे। उन्होंने मुझे किया भी। लेकिन जो बात मेरे मन में घर कर गई, वह मैं अभी तक भूल नहीं पाई, वह थी स्कूल के बाहर इन बच्चों के इंतजार में बैठी मांएं। एक मां सुबह 7 बजे से वहां बैठी थी। उसने बेटे का नाश्ता एक खास टिफिन में रखा, नीला नहीं, बल्कि हरे रंग का, क्योंकि नीला रंग बच्चे को बेचौन कर देता था। सुबह घर से निकलने से पहले बच्चे के साथ स्कूल की दिनचर्या की प्रक्रिया 7 से 8 बार तक दोहराई जाती है। उस मां ने मुझे यह सब शिकायत नहीं की, बल्कि शांत, सहज गर्व से बताया जैसे किसी ने बस अलग तरह से अपने बच्चे से प्यार करना सीख लिया हो। एक और मां ने मुझे बताया कि उसने प्रोजेक्ट मैनेजमैंट का करियर छोड़ा, जिसके लिए उसने जी-तोड़ मेहनत की थी। नौकरी इसलिए छोड़ी कि बेटी को एक ऐसी पूरी-वक्त मौजूदगी चाहिए थी, जो नौकरी के किसी शैड्यूल में फिट नहीं होती। 'उसे मेरी जरूरत थी कि मैं ही उसका शैड्यूल बन जाऊं', उस मां ने बस इतना कहा और जमीन की तरफ देख कर मुस्कुराई। मां जिसने नामुमकिन को मुमकिन किया रू एक मां की कहानी मुझे याद है, जिसके दिव्यांग बेटे को कई डाक्टरों ने पढने-लिखने में लाचार बताया। दिल पर पत्थर रख कर मां ने डाक्टरों की बातें सुनीं, उन्हें सहा। बच्चे को लेकर जताई गई लाचारी को मानने से इंकार करते हुए वह मां ही अपने बच्चे की थैरेपिस्ट बनी, उसकी टीचर बनी, उसकी जुबान बनी और आखिर में उसकी सुरीली आवाज बनी। आज वह नौजवान अपनी गायन कला के हुनर से सुरों के रस घोलता है, जिसके बोलों से लोगों की आंखें भर आती हैं।

बंगाल को पटरी पर लाने की चुनौती

संजय गुप्त। पश्चिम बंगाल में जैसे ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वैसे ही ममता बनर्जी ने उसका उग्र विरोध करना शुरू कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। शीर्ष अदालत ने एसआइआर को न केवल सही माना, बल्कि उसे जारी रखने के आदेश भी दिए। यही नहीं उसने इस प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों को भी सौंप दी। जब चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की तो उसका भी ममता ने विरोध किया, जबकि यदि चुनाव के पहले और चुनाव के समय हिंसा नहीं हुई तो इसका श्रेय चुनाव आयोग को ही जाता है।इसके बाद भी ममता ने अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। इस्तीफा देने से इन्कार करके उन्होंने बचकाने राजनीतिक व्यवहार का ही परिचय दिया है।निःसंदेह अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी मृत, स्थानांतरित और दोहराव वाले लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, लेकिन इसके आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी एसआइआर के कारण हारी। यह आरोप इस तथ्य से झूठा साबित होता है कि जिन 20 सीटों पर सबसे अधिक नाम काटे गए, उनमें से 13 में टीएमसी जीती।इससे इन्कार नहीं कि एसआइआर में कुछ विसंगतियां रही होंगी, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया सौ प्रतिशत सही नहीं होती, पर टीएमसी की हार के लिए एसआइआर को दोष देना इस सच से मुंह मोड़ना है कि ममता का शासन कुशासन का पर्याय बन गया था। 15 वर्षों से सत्ता पर आसीन ममता ने मुस्लिम तुष्टीकरण की हदें पार कर दी थीं। इसकी प्रतिक्रिया में हिंदू भाजपा के पक्ष में गोलबंद हुए और इसी कारण उसे अप्रत्याशित जीत मिली। टीएमसी की पराजय इस कारण भी हुई, क्योंकि खुद ममता भी अलोकप्रिय हो गई थीं। इसका कारण था उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से अवैध वसूली और लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करना।बंगाल में महिला असुरक्षा का मुद्दा भी सतह पर आया, क्योंकि आरजी कर मेडिकल कालेज की डाक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या और संदेशखाली में हिंसा एवं महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। इससे टीएमसी के प्रति सत्ता विरोधी माहौल और अधिक गहराया। ममता अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय जिस तरह यह कह रही हैं कि वे हारी नहीं, बल्कि उन्हें हराया गया है, वह उनकी खीझ ही है।बंगाल में आजादी के बाद पहले कुछ दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा, फिर वाम दल तीन दशक से भी अधिक समय तक सत्ता में रहे। जब वाम दलों का शासन कुशासन का पर्याय बना तो लोगों ने परिवर्तन के नारे के साथ उन्हें चुनौती देने वाली ममता का साथ दिया, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने भी वाम दलों वाले तौर-तरीके अपना लिए। इसका एक कारण यह भी रहा कि वाम दलों के तमाम नेता और कार्यकर्ता टीएमसी में आ गए थे। एक समय जो ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध करती थीं, वही सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लोभ में उनकी अनदेखी करनी लगीं। वे इस सच से इन्कार करती रहीं कि बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। वे घुसपैठियों का बचाव करने लगीं, जबकि हिंदू समाज यह देख रहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किस तरह असम की तरह बंगाल के सीमांत क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदल दी है।डेमोग्राफी में यह बदलाव सामाजिक असंतुलन पैदा करने और हिंदू अस्मिता को चोट पहुंचाने के साथ राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन रहा था। जैसे बंगाल में घुसपैठ एक चुनावी मुद्दा बनी, उसी तरह असम में भी और इसी कारण भाजपा वहां तीसरी बार जीती।बांग्लदेश में पिछले दिनों जो राजनीतिक उथलपुथल एवं हिंसा हुई और जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसका भी बंगाल के हिंदुओं पर असर पड़ा। उन्हें लगा कि बंगाल में राष्ट्रवादी विचारों वाली सरकार बननी चाहिए। पता नहीं क्यों ममता यह भूल गईं कि वाम दलों को भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने की कीमत चुकानी पड़ी थी? भाजपा ने घुसपैठियों को निकालने का नारा देकर जो नैरेटिव खड़ा किया, उसने इसलिए काम किया, क्योंकि बंगाली हिंदू अपने आसपास और खासकर सीमावर्ती जिलों में घुसपैठियों का दखल

देख रहे थे।बंगाल में राष्ट्रवादी विचारों वाली सरकार के गठन से न केवल राज्य का बिगड़ा माहौल सुधरना चाहिए, बल्कि घुसपैठ पर भी रोक लगनी चाहिए। आशा है कि भाजपा सरकार के रहते बांग्लदेश के साथ अनसुलझे मसले सुलझाने में भी मदद मिलेगी। बंगाल को राजनीतिक और चुनावी हिंसा की संस्कृति से मुक्त करना राज्य की नई सरकार के एजेंडे में खास तौर पर होना चाहिए। यह आसान नहीं, क्योंकि राज्य की राजनीति एक तरह से हिंसा और दबंगई के सहारे ही संचालित होती रही है। यह दुर्भाग्य की बात रही कि टीएमसी के शासन में भी यह अराजक राजनीतिक संस्कृति और फली-फूली। इसके लिए ममता अपने अलावा किसी अन्य को दोष नहीं दे सकतीं।बंगाल में चुनाव बाद जो हिंसा देखने को मिली और जिसके चलते कुछ भाजपा समर्थकों के साथ सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या की गई, उसके लिए टीएमसी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। भाजपा को सावधान रहना होगा कि उसके जो कार्यकर्ता और समर्थक टीएमसी से आए हैं, वे हिंसा और दबंगई की राजनीतिक संस्कृति न अपनाने पाएं। ध्यान रहे खुद सुवेंदु अधिकारी एक समय टीएमसी के प्रमुख नेता और ममता के विश्वासपात्र थे। स्पष्ट है कि भाजपा को अपने संग आए टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कार्य-व्यवहार के प्रति सतर्क रहना होगा। उसे यह भी देखना होगा कि टीएमसी का अराजक प्रवृत्ति वाला काडर भाजपा में न आने पाए। यदि भाजपा इसे लेकर सचेत नहीं रहती तो राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को खत्म करने में कठिनाई होगी। इसकी अनदेखी न की जाए कि चुनाव बाद हिंसा ने यही सिद्ध किया है कि भाजपा सरकार के सामने कानून एवं व्यवस्था को ठीक करना और ममता के कुशासन के असर को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। किसी राज्य का माहौल तब बदलता है, जब कानून एवं व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होती है। इसे दुरुस्त करके ही बंगाल को पटरी पर लाया जा सकता है।

क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ रही भाजपा

भाजपा उस राजनीतिक विमर्श को भी ध्वस्त कर रही है कि उसे चुनौती देने का जो काम देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नहीं कर पा रही, वह क्षेत्रीय दल बखूबी कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले दम बहुमत और कांग्रेस के 44 सीटों पर सिमट जाने से वह विमर्श शुरू हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने भी उसे बल प्रदान किया लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से वह कमजोर पडने लगा है। बेशक 2024 में भाजपा को मात्र 240 सीटों पर रोक देने में क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तमिलनाडु में द्रमुक और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने उसमें अहम भूमिका निभाई। बेशक कांग्रेस की सीटें भी 52 से बढ़ कर 99 हो गईं लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह क्षेत्रीय दलों के सहारे 'परजीवी' है। बात गलत भी नहीं थी, इन राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के सहारे ही चुनाव लडने को मजबूर है।बेशक हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें हैं, पर पहले दोनों राज्य लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से ज्यादा प्रभावी नहीं हैं। शायद इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा के निशाने पर क्षेत्रीय दल और उनकी सरकारें ज्यादा नजर आती हैं। कांग्रेस के अघोषित नेतृत्व वाला विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन स्वाभाविक ही भाजपा के 240 सीटों पर सिमट जाने को अपनी सफलता मान रहा था लेकिन उसके बाद से उसके हिस्से हार के झटके ही ज्यादा आए हैं। सिर्फ झारखंड और जम्मू-कश्मीर ही अपवाद रहे, जहां कांग्रेस की उपस्थिति का सत्ता राजनीति में ज्यादा अर्थ नहीं है। जम्मू-कश्मीर में नैशनल कान्फ्रैंस का ही दबदबा है तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का और विधानसभा चुनाव के बाद दोनों की ही कांग्रेस से दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटें जीत गया। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीतीं तो उद्धव की शिवसेना ने 9, जबकि शरद पवार की राकांपा ने 8। तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन 39 में 35 सीटें जीतने में सफल रहा। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को 12 सीटों पर समेटते हुए 42 में से 29 लोकसभा सीटें जीत लीं। अलग लड़ी कांग्रेस भी एक सीट जीत गई। 20 सीटों वाले केरलम् में भी कांग्रेस नीत यू.डी.एफ. 18 सीटें जीत गया, जबकि तत्कालीन सत्तारूढ़ एल.डी.एफ. के हिस्से 1 ही सीट आई। भाजपा भी पहली बार अपना खाता खोलने में सफल रही। बेशक यू.डी.एफ. की 18 में से 14 सीटें कांग्रेस की रहीं लेकिन केरलम् में गठबंधन राजनीति एक अनिवार्यता रही है। इसलिए कांग्रेस की सीटें बढ़ कर 99 हो जाने के बावजूद भाजपा के तेज रफ्तार विस्तार पर नियंत्रण में क्षेत्रीय दलों की अहम् भूमिका है। बेशक चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी, नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड, जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोकदल, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, स्वर्गीय अजित पवार की राकांपा के अलावा तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक, भाजपानीत राजग में शामिल हैं लेकिन नवीन पटनायक का बीजू जनता दल, हेमंत सोरेन का झामुमो, लालू-तेजस्वी का राजद, अखिलेश यादव की सपा, एम.के. स्टालिन का द्रमुक, उमर अब्दुल्ला की नैशनल कान्फ्रैंस, अरविंद केजरीवाल की 'आप' और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम बड़े क्षेत्रीय दल उससे दूरी बनाए हुए हैं। संयोग कहें या प्रयोग, 2024 से ही इन दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पटनायक के बीजद की दशकों पुरानी सत्ता ओडिशा में तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनाव में ही उखाड़ फैंकी थी, महाराष्ट्र में चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में पासा पलट दिया, जब विपक्ष हाशिए पर चला गया। भारतीय राजनीति में धूमकेतु की तरह चमके केजरीवाल की 'आप' से भी भाजपा ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता छीन ली। पिछले साल के अंत में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ही ऐसे ही एकतरफा परिणाम आए, जिनके लिए विपक्ष सीधे-सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवालिया निशान लगा रहा है। अरसे से ई.वी.एम. पर संदेह जताता रहा विपक्ष अब एस.आई.आर. प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम काटे जाने को भाजपा की अप्रत्यक्ष चुनावी मदद करार दे रहा है। बेशक चुनाव आयोग की भूमिका से जुड़े विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक गए हैं लेकिन चुनाव परिणाम नहीं बदल रहे। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी का सत्ता दुर्ग अभेद्य माना जा रहा था। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 पार का नारा दे कर 77 सीटों पर थम गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को और बड़ा झटका दिया था। उसके चलते माना जा रहा था कि इस बार भाजपा 100 पार भले चली जाए, पर ममता की सत्ता नहीं डिगेगी लेकिन 2021 के चुनाव परिणाम 2026 में लगभग पलट गए। बेशक तमिलनाडु की परंपरागत द्रविड़ राजनीति के विरुद्ध त्रिशंकु विधानसभा में चमत्कारिक रूप से सबसे बड़े दल के रूप में उभरी अभिनेता जोसेफ विजय चंद्रशेखर की टी.वी.के. भी एक क्षेत्रीय दल ही है लेकिन दशकों पुराने स्थापित क्षेत्रीय दलों-द्रमुक और अन्नाद्रमुक तो सत्ता के खेल से बाहर नजर आ रहे हैं।

तीन राज्यों में उथल-पुथल और बदलाव

पी. चिदम्बरम

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों ने 3 राज्यों-केरलम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक नाटकीय बदलाव ला दिया है। असम और पुड्डुचेरी ने यथास्थिति के लिए वोट दिया है। चुनावों पर एक ही कहानी लिखना संभव नहीं है। हर राज्य ने एक अलग कहानी पेश की है। केरलम एक सीधी कहानी है। यू.डी.एफ. और एल.डी.एफ. दशकों से राज्य में बारी-बारी से शासन कर रहे हैं। यह सिलसिला 2021 में तब टूटा, जब पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एल.डी.एफ. को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। कांग्रेस ने एक नया नेतृत्व (पी.सी.सी. और सी.एल.पी.) स्थापित किया और पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में एक सच्चे विपक्ष के रूप में नए जोश के साथ काम किया है। इसका प्रतिफल दिखाई दे रहा है। यू.डी.एफ. का दायित्व है कि वह शासन करे और ऐसे परिणाम दे जिससे यू.डी.एफ. के सहयोगी एकजुट रहें और धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक प्रगति और समृद्धि तथा संघवाद को आगे बढ़ाया जा सके। तमिलनाडु की कहानी जटिल है। कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों के समर्थन से द्रमुक 2021 में एक ठोस बहुमत के साथ चुनी गई थी। इसने निरूसंदेह 2 मोर्चों पर परिणाम दिए, आर्थिक विकास और कल्याणकारी उपाय। जाहिर है, मतदाता के मन में अन्य कारक थे। एक अज्ञात कारक था जोसेफ विजय का प्रवेश, जो एक फिल्म हीरो हैं और जिनके प्रशंसकों का एक बड़ा समूह है, खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से एक हवा चलनी शुरू हुई। इसने गति पकड़ी और मतदान की तारीख से पहले अंतिम 10 दिनों में एक

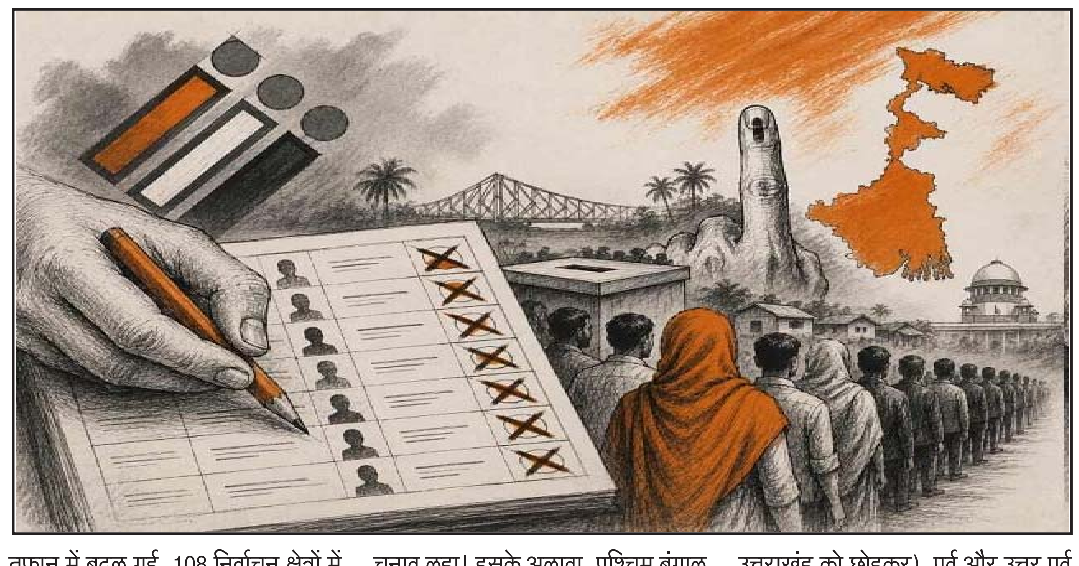

तूफान में बदल गई, 108 निर्वाचन क्षेत्रों में फैल गई लेकिन उससे आगे नहीं गई। दो साल पुरानी एक राजनीतिक पार्टी के लिए यह एक शानदार शुरुआत थी। अधिकांश उम्मीदवार अज्ञात नाम और चेहरे थे और कुछ ने ही प्रचार किया। उम्मीदवार हर जगह 'विजय' थे। विजय के कुछ छोटे भाषण, वीडियो मीम्स और कई फिल्मी गाने ही 'प्रचार' थे। टी.वी.के. को साधारण बहुमत से 11 सीटें कम मिलीं, लेकिन राष्ट्रपति शासन को टालने और एक और चुनाव से बचने के लिए, कांग्रेस (5), भाकपा (2), माकपा (2) और वी.सी.के. (2) ने समर्थन देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल वह वास्तविक कहानी है, जिसमें देश की दिशा बदलने की क्षमता है। पश्चिम बंगाल में धर्मनिरपेक्ष दल-कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और माकपा ने पिछले 10 वर्षों में मजबूत हुई भाजपा के खिलाफ अलग-अलग चुनाव लड़ा। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में एस.आई.आर. ने बड़ी संख्या में मतदाताओं को मिटा दिया और लोकतंत्र पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां बेटा-बेटी एक मतदाता था लेकिन पिता-माता नहीं थे। परिवारों को मतदाताओं और गैर-मतदाताओं में विभाजित किया गया था। न्यायपालिका और अस्थायी न्यायिक उपायों ने लाखों मतदाताओं को निराश किया और हजारों लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। एस.आई.आर. के अलावा, 3 कार्यकालों का बोझ तृणमूल कांग्रेस के गले में एक बड़ा पत्थर था।

तृणमूल कांग्रेस की हार गंभीर घटनाक्रमों का संकेत देती है-भाजपा एकमात्र पार्टी है या गठबंधन सरकारों में पश्चिम (महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा), हिंदी पट्टी के अधिकांश हिस्सों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर), पूर्व और उत्तर पूर्व में शासन कर रही है। प्रतीकात्मक रूप से, विंध्य पर्वतमाला भाजपा के 5 दक्षिणी राज्यों में प्रवेश के लिए एक बाधा है। केरलम और तमिलनाडु में प्रवेश के उसके अथक प्रयासों को मतदाताओं ने दृढ़ता से नकार दिया (भाजपा को क्रमशः 3 और 1 सीट मिली)। हालांकि, बाकी भारत पर उसका नियंत्रण लगभग पूरा हो चुका है।2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 240 सीटें जीतने के बावजूद, भाजपा ने संसद में निम्नलिखित विवादास्पद विधेयक पारित किए हैं।-वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025,-जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय (संशोधन) अधिनियम, 2025,-कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 और-राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025। अन्य विवादास्पद विधेयक आने वाले हैं, जिनमें अलोकतांत्रिक 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक भी शामिल है। संख्या बल की कमी के बावजूद, भाजपा ने महिलाओं के आरक्षण के लिए एक विधेयक को निरस्त करने और फिर से अधिनियमित करने के लिए विवादास्पद संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश किया, जिसे सितम्बर 2023 में पारित किया गया था। नए विधेयक का वास्तविक उद्देश्य परिसीमन को आगे बढ़ाना और प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या को बदलना था। यह विधेयक इंडिया ब्लॉक द्वारा हरा दिया गया था। यदि भाजपा अपनी जीत का सिलसिला जारी रखती है, तो सरकार संसदीय प्रणाली के आवरण में एक सत्तावादी राज्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रयास करेगी। भाजपा का अगला लक्ष्य एक एकात्मक संविधान (संघवाद को दफनाना), एक प्रमुख विचारधारा के रूप में हिंदुत्व (धर्मनिरपेक्षता को दफनाना), आर्थिक मॉडल के रूप में पूंजीवाद (कल्याणकारी राज्य को दफनाना) और अंततरू एक-दलीय राज्य (लोकतंत्र को दफनाना) होगा। विपक्षी दलों को मजबूती से पीछे धकेलना होगा। भाजपा रूढ़िवादी ध्रुव होगी। भारत को एक लोकतांत्रिक, संघीय और धर्मनिरपेक्ष देश बने रहने के लिए अन्य राजनीतिक विकल्प और विकल्प संरक्षित किए जाने चाहिएं। इंडिया ब्लॉक ने 2024 में आंशिक सफलता हासिल की लेकिन उस गति को आगे बढ़ाने में विफल रहा। ब्लॉक संघर्ष करता और लडखड़ाता हुआ प्रतीत होता है लेकिन भाजपा को चुनौती देने का यही एकमात्र साधन है। चुनाव के बाद, ममता बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस) ने इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने का वादा किया है। एम.के. स्टालिन (द्रमुक) ने ब्लॉक के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा।

चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी समेत 6 एमएलए ने ली मंत्री पद की शपथ

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार रविवार को लखनऊ में संपन्न हुआ। लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में राजनीतिक हलचल के बीच कई नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को प्रमोशन भी दिया गया। इस विस्तार को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी रणनीतिक कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। नए मंत्रियों के रूप में भूपेंद्र चौधरी, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत और सुरेंद्र दिलेर ने शपथ ली। इनके अलावा सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिन्हें प्रमोशन देकर कैबिनेट स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार की ओर से किए गए इस फेरबदल में सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण, तीन ओबीसी और दो दलित समाज से आते हैं। इस तरह भाजपा ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। यह मंत्रिमंडल विस्तार उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से जनभवन में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ही यह स्पष्ट हो गया था कि लंबे समय से प्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार अब होने जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में पिछले कई महीनों से मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन पर अब जाकर विराम लगा है। भाजपा ने इस विस्तार में सामाजिक प्रतिनिधित्व को प्रमुख आधार बनाया है। ओबीसी, दलित और ब्राह्मण समुदायों को संतुलित प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर

प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जातीय समीकरण चुनावी राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।इस विस्तार में कुछ मौजूदा मंत्रियों को भी पदोन्नति दी गई है। सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल को राज्य मंत्री से कैबिनेट स्तर पर प्रमोट किया गया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव उनके प्रदर्शन और संगठन में उनकी भूमिका को देखते हुए किया गया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भाजपा प्रदर्शन आधारित राजनीति को भी बढ़ा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महोबा की विधायक आशा मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि वर्षों से पार्टी और संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी पीड़ादायक है। उनकी इस प्रतिक्रिया को संगठन के भीतर असंतोष के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है। भाजपा लगातार अपने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नए संदेश देने की कोशिश कर रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि वह अलग-अलग सामाजिक समूहों को साथ जोड़कर अपना जनाधार और मजबूत करे। नए चेहरों को मौका देकर भाजपा यह भी संकेत देना चाहती है कि वह नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।इस विस्तार को सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। कई नेताओं को शामिल कर और कुछ को प्रमोट कर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं को भी उचित अवसर मिलेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि पार्टी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग और क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम कर रही है। योगी कैबिनेट का यह विस्तार केवल मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का कदम नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देता है। भाजपा यह दिखाना चाहती है कि वह उत्तर प्रदेश में स्थिर और संतुलित सरकार चला रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नए मंत्रियों के जरिए सरकार जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी काम कर पाती है और क्या यह बदलाव आने वाले चुनावों में भाजपा को राजनीतिक बढ़त दिला पाएगा।

इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया द्वारा मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह आयोजित

लखनऊ (यूएनएस)। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से ईदगाह, लखनऊ में एक भव्य 'सम्मान समारोह' आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्हों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। इस समारोह में लगभग 300 विद्यार्थियों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें सीएमएस, लामार्टिनियर कॉलेज, क्राइस्टचर्च कॉलेज, कैथेड्रल कॉलेज, द लखनऊ पब्लिक कॉलेजिएट, सेंटमेरी इंटर कॉलेज, इरम पब्लिक स्कूल, और शाहीन अकादमी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राएँ शामिल थे। इस अवसर पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहाकि इस समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाना और उन्हेंआगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि लखनऊ को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही विद्यार्थी भविष्य में देश के अधिकारी, शिक्षक, व्यापारी और नेता बनेंगे तथा भारत की तरक्की और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने विद्यार्थियों को सफलता के लिए अनुशासन और मेहनत को सबसे जरूरी बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें अपनाने की सलाह दी, जैसे पढ़ाई में नियमितता बनाए रखना। ध्मोबाइल और स्क्रीन का कम इस्तेमाल करना। कक्षा में नियमित पढ़ाई करना। ध्किताबें पढ़ने की आदत डालना। नियमित लिखने का अभ्यास करना। समय पर दोहराई (रिवीजन) करना। सैंपल पेपर हल करना। ध्पिछले 10 वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करना। रोज 5 से 6 घंटे स्व अध्ययन करना।

शहीद अब्दुल रफीक खान की याद में उमड़ा व्यापारियों का सैलाब

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी के ऐतिहासिक नक्खास बाजार में आयोजित शहीद अब्दुल रफीक खान की 21वीं पुण्यतिथि मात्र एक शोक सभा नहीं, बल्कि व्यापारियों के स्वाभिमान और एकजुटता का एक बुलंद उद्घोष बनकर उभरी। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य वक्ताओं ने अपने ओजस्वी विचारों से शहीद की विरासत को नई ऊंचाई दी। साम्प्रदायिक एकता का रूहानी संदेश, साहब एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और प्रमुख समाजसेवी अब्दुल वहीद फारुकी ने अपने संबोधन में समाज की बुनावट और भाईचारे पर गहरा जोर दिया। उन्होंने कहा, शहीद अब्दुल रफीक खान की शहादत किसी एक धर्म या वर्ग के लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने इंसानियत और हक की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया था। यह बाजार उस साझी विरासत का गवाह है जहाँ हिंदू-मुस्लिम की दीवारें ढह जाती हैं और सिर्फ इंसानियत का रिश्ता बचता है। हमें इस गुलदस्ते जैसी एकता को महफूज रखना है, क्योंकि यही हमारे मुल्क की असली रूह है। बाजार की रौनक तभी तक है, जब तक हमारा आपसी प्रेम सलामत है। वही भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं व्यापारी संगठन के संरक्षक अजय त्रिपाठी मुन्ना ने एक अभिभावक के रूप में व्यापारियों में आत्मविश्वास जगाते हुए कहा की इतिहास गवाह है कि जब-जब दबे-कुचले लोगों की आवाज दबाई गई, तब-तब शहीद अब्दुल रफीक खान जैसे नायकों ने अपने रक्त से न्याय की इबारत लिखी। शहीद रफीक साहब ने व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था। आज मैं आप सबको यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि व्यापारी समाज अब अकेला नहीं है। संगठन आपकी ढाल है। हम शासन और प्रशासन के बीच सेतु बनकर खड़े हैं, ताकि किसी भी छोटे या बड़े दुकानदार का उत्पीड़न न हो सके। शहीद के परिवार की खुशहाली और व्यापारियों का सम्मान ही हमारी प्राथमिकता है।

अखिलेश राज में 'कटियाबाजों' को मिला संरक्षण-शर्मा

अखिलेश सरकार ने किया बिजली ईको सिस्टम में बबूल बोने का काम

खराब ट्रांसफॉर्मर और जर्जर तार सपा की देन, यूपी में 165 लाख नए बिजली कनेक्शन का रिकॉर्ड

लखनऊ (यूएनएस)। प्रदेश भर में अज्ञात लोगों द्वारा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को श्कटियाबाजश् बताते हुए लगाए गए पोस्टरों के बीच अब योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भी सपा पर तीखा हमला बोला है। सपा राज में बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सपा सरकार ने प्रदेश के बिजली तंत्र को पूरी तरह बर्बाद करने का काम किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में नेताओं, गुंडों और माफियाओं को कटिया मारकर बिजली चलाने का खुला लाइसेंस दे दिया गया था। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के पूरे बिजली ईको सिस्टम में बबूल बोने का काम किया।ऊर्जा मंत्री ने सबसे बड़ा हमला बिजली चोरी को लेकर बोला। उन्होंने कहा कि सपा शासन में नेताओं और उनके करीबी लोगों को कटियाबाजी कर मुफ्त बिजली बांटने की खुली छूट थी। श्हर जगह इनके गुंडे और माफिया बिजली के वितरक बन गए थे। खुद कटियाबाजी करते थे और दूसरों को भी

कटियाबाजी करवाते थे।श् उन्होंने दावा किया कि संभल और मथुरा समेत कई जिलों में सुनियोजित ढंग से बिजली चोरी कराई जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने ऐसे कटियाबाजों पर कड़ी कार्रवाई कर लगाम लगाने का काम किया।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सपा सरकार के समय लगाए गए ट्रांसफॉर्मर, तार और खंभे बेहद खराब गुणवत्ता के थे, जो आए दिन फुंक जाते थे। आज भी प्रदेश जिन खराब तारों और जर्जर खंभों की समस्या से जूझ रहा है, वह सपा सरकार की ही देन है। योगी सरकार ने पिछले वर्षों में बिजली व्यवस्था में बड़े सुधार किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को बेहतर बिजली ढांचा देने का काम लगातार जारी है। योगी सरकार ने इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को सुधारने का बीड़ा उठाया है। तकनीकी सुधारों और डिजिटल सिस्टम के जरिए मानवीय हस्तक्षेप कम किया गया ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और जनता को राहत मिले।एके शर्मा ने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने बिजली खरीद में भी घोटाले किए। उन्होंने कहा कि आज सरकार जिस दर पर बिजली खरीद रही है, उससे भी ज्यादा महंगी दरों पर सपा सरकार ने बिजली खरीद के करार किए थे। इसका खामियाजा आज भी प्रदेश की जनता भुगत रही है और आने वाले वर्षों तक लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना मेरिट और गलत तरीके से भर्तियां की गईं, जिसके चलते भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुईं। ऐसे कर्मचारियों ने पहले दिन से ही जनता को लूटने का काम शुरू कर दिया था और हर स्तर पर उपभोक्ताओं का शोषण हुआ। सपा सरकार पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के भविष्य निधि घोटाले का भी आरोप लगाया। हजारों करोड़ रुपये का पीएफ गलत जगह निवेश कर कर्मचारियों का पैसा डुबाने की कोशिश की गई। यही कारण था कि बिजली कर्मियों में असुरक्षा और भ्रष्टाचार बढ़ा।

कैंसर फ्री वूमेन भारत यात्रा को राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी

लखनऊ (यूएनएस)। स्त्री वेलफेयर फाउण्डेशन की ओर से आयोजित 'आनंदी मां एक जीवन बचाओ अभियान' एवं कैंसर फ्री वूमेन भारत यात्रा के अंतर्गत रविवार को राजधानी में भव्य जन-जागरूकता रैली निकाली गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रैली की शुरुआत की। रैली की शुरुआत जनभवन से हुई, जो महात्मा गांधी मार्ग, अटल चौक, पार्क रोड, डॉ. भीमराव आंबेडकर मार्ग, सिविल चौराहा और भानुमति रोड होते हुए सरोजनी नायडू मार्ग चौराहे पर संपन्न हुई। रैली के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, कैंसर जागरूकता और स्वस्थ भारत के संकल्प का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम के दौरान आनंदीबेन पटेल ने संस्था के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य केवल परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। राज्यपाल ने कहा कि समय पर जांच और जागरूकता के माध्यम से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने संस्था को भविष्य में भी व्यापक स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। रैली में 130 से अधिक लोगों ने सहभागिता की और 'स्वस्थ मां दृ सुरक्षित भविष्य' का संदेश दिया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राज्यपाल से हुई विशेष बैठक में डॉ. सुमेधा नीलू त्रिवेदी, डॉ. रमेश कुमार सिंह, खुशबू तिवारी, अविका तिवारी, डॉ. अवधेश सिंह, डॉ. मयंक मोहन, डॉ. किरन दास, डॉ. इंदुलता और डॉ. शैली महाजन सहित कई चिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नोएडा में मजदूरों के आंदोलन का समर्थन में मजदूर संगठनों का प्रदर्शन

लखनऊ (यूएनएस)। राजधानी लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर मजदूर संगठनों ने रविवार को प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बीते दिनों नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन का समर्थन और उन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हम इकट्ठा हुए हैं। उनकी तैयारी चारबाग से सीएम आवास तक जाने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन से पहले ही उनके नेताओं को गृहजनपदों में नजरबंद कर दिया गया। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले विभिन्न श्रमिक संगठनओं ने चारबाग से सीएम आवास तक मार्च निकालने का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारी हाथों में लाल झंडा और पोस्टर लेकर चारबाग से मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े कि उन्हें बैरिकेडिंग कर पुलिस ने रोक लिया। प्रदर्शन में शामिल शांतम निधि ने कहा कि हम लोग चारबाग से मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे थे। मगर हम लोगों को पुलिस ने रोक लिया गया। हमारे मजदूर साथी आगे न बढ़ पाएं इसलिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। हम सभी प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोग नोएडा के उन मजदूरों के लिए सड़क पर उतरे हैं जो मिनिमम डेली वेजेस के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें से कई मजदूर और उनके नेता गायब हैं। इसके अलावा 8 सोशल एक्टिविस्ट लापता है जिनका उस प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं था। इस प्रदर्शन का जब हमने आह्वान किया तो हमारे नेताओं को उनके गृह जनपदों में नजरबंद कर दिया गया। लखनऊ भाकपा माले के इंचार्ज रमेश सेंगर ने कहा कि यूपी में मौजूदा सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है। पिछले दिनों जब गैस की कीमत थी, उस समय वेतन बढ़ोतरी और 8 घंटा काम को लेकर नोएडा के श्रमिकों ने आंदोलन किया था। औद्योगिक क्षेत्र में जिन मजदूरों ने काम किया। जब प्रदर्शन किया तो उनका दमन हुआ। सैकड़ों मजदूरों को जेल में डाल दिया गया। उनके नेताओं का पता नहीं चल रहा है। इस समय देश में आवाज उठाना आंदोलन करना मुश्किल हो गया है। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। 12 जनपदों में हमारे

साथियों को नजरबंद कर दिया गया। रमेश सेंगर ने कहा- भारत में लोकतंत्र है यह देश संविधान से चलना चाहिए, मगर ये लोग बुलडोजर से चला रहे हैं। हमारी मांग है कि नोएडा के गिरफ्तार किए गए मजदूरों को रिहा किया जाए। जो लापता हैं, उनकी तलाश की जाए। मजदूरों को सम्मानजनक वेतन दिया जाए और 8 घंटे ही काम लिया जाए। लंबी लड़ाई के बाद मजदूरों के अधिकार के लिए जो कानून बने थे, उनका पालन हो।

जब 9 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 9 महीने में नए मंत्री क्या कर लेंगे? मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव का तंज

लखनऊ (यूएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार 9 साल में कुछ नहीं कर सकी, तो नए मंत्री 9 महीनों में क्या कर लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच श्एक्सश् पर पोस्ट कर सवाल किया कि मंत्रिमंडल में केवल 6 रिक्तियां हैं, इससे ज्यादा तो दूसरे दल से पाला बदल कर आए लोग हैं, क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? यादव ने कहा कि एक समाज के कई विधायकों में से किसी एक को चुना जाएगा तो चुनने का आधार क्या होगा?, अगर ऐसा हुआ तो बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा?, उनकी उपेक्षा व अपमान को क्या कुछ ले-देकर शांत करा जाएगा? या उन्हें भी ये अहसास करा दिया जाएगा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है? उन्होंने कहा कि बाकी छूटे हुए लोग क्या अपने को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे? और वे अपने चुनाव

क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक बचेंगे क्या? इसके अतिरिक्त प्रश्न ये भी है कि उनके अपने दल के जो लोग मंत्री बनने के इंतजार में सूखकर कांटा हो गये हैं, उन बेचारों का क्या होगा? यादव ने यह भी कहा कि जिन वर्तमान मंत्रियों के विभाग कम किए जाएंगे तो क्या इससे जनता के बीच ये संदेश नहीं जाएगा कि वो नाकाम रहे, इसलिए उनसे मंत्रालय छीन लिया गया है? ऐसे मंत्री तो बिना लड़े ही क्या अपना चुनाव हार नहीं जाएंगे? सपा प्रमुख ने कहा कि साथी दलों को प्रतीक्षा के स्थान पर और कुछ मिलेगा या फिर उनको ये कहकर उपेक्षित कर दिया जाएगा3 तुम थे जिनके सहारे, वो हुए न तुम्हारे... वो तो ठग हैं पुराने... तुम ये सच न जाने। सपा अध्यक्ष ने सवाल किया कि जनता यह भी पूछ रही है कि आखिरी 9 महीनों में ये मंत्री क्या कर लेंगे, जब 9 वर्षों में सरकार कुछ नहीं कर सकी। यादव ने कहा कि ये भी वही करेंगे जो भाजपा सरकार करती आई है-भ्रष्टाचार और अत्याचार। पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) पर वार-ही-वार। महंगाई और बेरोजगारी की मार। ये जीना दुश्वार कर देंगे।

जल जीवन मिशन को भरपूर बजट, जल्द पूरा होगा लक्ष्य

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन हर घर नल योजना न केवल एक सरकारी योजना है बल्कि ग्रामीण जीवनशैली में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस मिशन को युद्धस्तर पर लागू किया जा रहा है। केंद्र से उत्तर प्रदेश के लिए 13,425 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार भी ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को करीब 15 हजार करोड़ रुपये वर्ष 2026-27 में योजनाओं को पूरा करने के लिए देगी। इस 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में कोई बाधा नहीं आएगी। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में 2.62 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जाए। इस लक्ष्य को अब जल जीवन मिशन 2.0 के जरिए हासिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बीच जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुका है। इसमें जल जीवन मिशन की डेड लाइन जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश को 13,425 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।एसडब्ल्यूएसएम, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के विशेष सचिव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रभास कुमार ने बताया कि मिशन के नए स्वरूप और बजट के साथ नई जिम्मेदारियों को भी जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत प्रदेश में जल गुणवत्ता परीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आईजीआरएस, अप्रैल में रामपुर ने फिर मारी बाजी

तेजी से धरातल पर उतारे जा रहे विकास कार्य, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, हर वर्ग का उत्थान

लखनऊ (यूएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पिछले नौ वर्षों से समग्र विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है बल्कि समाज के हर वर्ग का उत्थान भी किया जा रहा है। सीएम के सपनों को साकार करने में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली आईजीआरएस अहमभूमिका निभा रहा है। आईजीआरएस से जनसुनवाई, जन कल्याणकारी योजनाओं और राजस्व कार्यों की निगरानी की जा रही है, जिससे जिलों को बेहतर प्रशासनिक मानक स्थापित करने में मदद मिल रही है। आईजीआरएस की अप्रैल माह की रिपोर्ट में प्रदेशभर में रामपुर ने 138 अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि पीलीभीत ने दूसरा और श्रावस्ती के साथ अमेठी ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हाथरस, बरेली, हमीरपुर, बदायूं, बाराबंकी और बलिया ने टॉप टेन जिलों में जगह बनायी है।आईजीआरएस द्वारा हर माह जिलों के राजस्व कार्यों, विकास कार्यों और जन शिकायत की सुनवाई की रिपोर्ट जारी की जाती है। आईजीआरएस द्वारा प्रदेशभर के जिलों में 49 विभागों के 109 कार्यक्रमों की विभिन्न मानकों के आधार पर समीक्षा की जाती है। जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। आईजीआरएस की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार रामपुर ने मानक पूर्णांक 140 नंबर के सापेक्ष 138 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका रेश्यो 98.57 प्रतिशत है।डीएम रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि आईजीआरएस की रिपोर्ट जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिन्होंने प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों और राजस्व प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा अनुरूप रामपुर में विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। आईजीआरएस के जरिये मिली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। रामपुर पिछले चार माह से पहले स्थान पर है।पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले में प्राथमिकता के आधार पर जनसुनवाई में शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। जनशिकायतों के निस्तारण दर में सुधार हो रहा है। पीलीभीत लगातार चार माह से प्रदेश में दूसरा स्थान बनाए हुए है। आईजीआरएस की अप्रैल माह की रिपोर्ट में भी पीलीभीत पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। पीलीभीत ने पूर्णांक 140 नंबर के सापेक्ष 137 अंक प्राप्त किये।

न्यूज डायरी

विशेश्वरगंज में कौशल विकास मिशन केंद्र खुला,विधायक प्रतिनिधि ने किया उद्घाटन

बहराइच (यूएनएस)। विशेश्वरगंज के कंछर में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 10 मई 2026 को किया गया। विधायक प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी ने इसका उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। यह केंद्र दसवीं पास बेरोजगार युवाओं को फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में निशुल्क प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण का संचालन एचएसआरजी संस्था द्वारा किया जाएगा। इससे युवाओं को तकनीकी दक्षता प्राप्त होगी और रोजगार व स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उद्घाटन के अवसर पर विधायक प्रतिनिधि निशंक त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा रही है। इस अवसर पर केंद्र प्रबंधक सर्वेश शुक्ला, पवन शुक्ला, आदर्श पाठक, मुकेश तिवारी, मुकेश शुक्ला, अमर मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना की और इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए लाभकारी बताया। उपस्थित लोगों ने केंद्र के सफल संचालन की कामना की।

4 भाइयों के घर एक साथ चोरी, दहशत में ग्रामीण

बहराइच (यूएनएस)। रुपईडीहा थाना क्षेत्र के देवरा गांव में शनिवार रात एक ही परिवार के चार भाइयों के घरों में लाखों रुपये की चोरी हुई। चोरों ने घरों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात चुरा लिए। सुबह जब परिवार के सदस्य जागे, तो उन्हें घरों के दरवाजे खुले और कमरों के ताले टूटे मिले। पीड़ितों के अनुसार, चोर रात के समय घर में घुसे और अलग-अलग कमरों के ताले तोड़ दिए। उन्होंने अलमारियों और बक्सों में रखे नकदी तथा जेवरात चुरा लिए। कमरों के अंदर सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित ओमप्रकाश ने बताया कि उनके कमरे से सोने का बाला, मंगलसूत्र, हथिया तोड़ा, दो जोड़ी पायल और 23 हजार रुपये नकद चोरी हुए हैं। अमृत लाल के अनुसार, उनके कमरे से चार जोड़ी पायल, कमर फूल, मंगलसूत्र, बाला और डेढ़ लाख रुपये नकद समेत अन्य सामान चोरी हो गया। कुंज बिहारी के कमरे से सोने का बाला, मंगलसूत्र, पायल, दस बिछिया और हजारों रुपये नकद चुराए गए। उषा देवी के कमरे से सोने की माला, एक जोड़ी पायल और 10 हजार रुपये नकद चोरी हुए हैं। परिजनों ने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 15 से 18 लाख रुपये की चोरी हुई है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर चोरी का खुलासा करने और चोरी हुए सामान की बरामदगी की मांग की है। गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीण चिंतित हैं। उन्होंने पुलिस गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। रुपईडीहा थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत ने बताया कि मौके पर पहुंचकर जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बने

रायबरेली (यूएनएस)। ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे को रविवार को कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने से पहले वह रायबरेली से लखनऊ जाते समय रास्ते में स्थित हनुमान जी के मंदिर चूरूवा मंदिर में पूजा किया दर्शन किया। फिर लखनऊ के लिए रवाना हुए। शपथ के दौरान मनोज कुमार पांडे ने अपना पुरानी बुनावट का गमछा डाले रहे, जो हमेशा उनके गले में रहता है। सपा सरकार में भी ऐसा ही गमछा पहने रहते थे। योगी सरकार में मंत्री बनाए गए मनोज कुमार पांडे ने कहा, मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे यह जिम्मेदारी दी है। पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देगी, उसका हम पालन करेंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जो दिशा-निर्देश देगी उसपर काम करेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा, यह उनका मानसिक असंतुलन है। जब पूरे देश का जनादेश आज भाजपा, राष्ट्र और सनातन के स्तंभ के पक्ष में है तो समाजवादी पार्टी इस तरह के सवाल उठाती है। सुबह मनोज कुमार पांडे रायबरेली अपने आवास से लगभग 11.05 पर सुरक्षा काफिले के साथ लखनऊ के लिए निकले हुए थे तकरीबन 12.00 बजे उन्होंने रायबरेली सीमा पर स्थित चूरूवा हनुमान मंदिर में पहले दर्शन किया माथा टेका और पूजा की उसके बाद वह राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हुए, जहां पर उन्होंने 3.30 पर मंत्रिमंडल के विस्तार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली।

आवारा कुत्तों के हमले से मोर की मौत, ग्रामीणों ने बताया खतरा बढ़ा

रायबरेली (यूएनएस)। जनपद में आवारा कुत्तों के हमले में एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। यह घटना रविवार को नसीराबाद थाना क्षेत्र के भीख बभनपुर गांव में सामने आई। जानकारी के अनुसार, रविवार को भीख बभनपुर गांव के समीप मोर दाना चुग रहा था। तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। मोर ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुत्तों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मोर के शव को कब्जे में लेकर वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे वन्य जीव और छोटे बच्चे भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वन विभाग की टीम इस मामले की जांच कर रही है।

ऊंचाहार विधायक योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने, गदागंज क्षेत्र में खुशी की लहर

रायबरेली (यूएनएस)। जिले की ऊंचाहार विधानसभा के विधायक डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर गदागंज चौराहे पर जश्न मनाया गया। यह जश्न विकास खंड दीनशाहगौरा के गदागंज चौराहे पर स्थित ग्राम प्रधान अलीपुर चकराई पुष्पा सिंह के आवास पर आयोजित किया गया। इस दौरान 21 गोले बांटे गए और लोगों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद प्रखंड के संरक्षक प्रेम श्रीवास्तव, प्रधान संघ अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान जलालपुरधई रनबहादुर सिंह, अर्पित गुप्ता, आशीष तिवारी, रज्जू दादा, सत्यनारायण, रुद्रभान सिंह, प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र बहादुर सिंह उर्फ राजू सिंह, अक्षय तिवारी उर्फ भाई जी, अवधेश तिवारी, राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह सहित अलीपुर चकराई के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। उपस्थित लोगों ने डॉ. मनोज पाण्डेय और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारे लगाए।

मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन, 46 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण

रायबरेली (यूएनएस)। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देहली में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कुल 46 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया। मेले में क्षेत्र के ग्रामीणों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और चिकित्सकीय परामर्श लिया। चिकित्साधिकारी डॉ. पूनम शर्मा ने सभी मरीजों की जांच की और उन्हें आवश्यक दवाएं प्रदान कीं। डॉ. शर्मा ने मरीजों को मौसमी बीमारियों से बचाव, स्वच्छता और संतुलित खानपान के प्रति जागरूक किया। आरोग्य मेले में बुखार, सर्दी-जुकाम, ब्लड प्रेशर और अन्य सामान्य बीमारियों से संबंधित मरीजों की जांच की गई। चिकित्साधिकारी ने बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच और समय पर उपचार से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान एएनएम आराधना वर्मा, लैब असिस्टेंट अरविंद कुमार श्रीवास्तव सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

अवैध तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार

रायबरेली (यूएनएस)। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गश्त के दौरान पूरे कुटी मोड़ के पास की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।जानकारी के अनुसार, कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक राहुल कुमार मिश्रा पहाड़पुर मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पूरे कुटी मोड़ के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही युवक ने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से एक 315 बोर का देसी तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान भदोखर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी विवेक सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह के रूप में हुई है।

बोर्ड की बैठक का सभासदों ने किया विरोध

जौनपुर। नगर पंचायत कजगांव कार्यालय में सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक में सभासदों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान की अध्यक्षता में उक्त नगर पंचायत बोर्ड की बैठक चल रही थी कि इसी दौरान तमाम सभासदों ने बोर्ड बैठक का विरोध करने लगे।सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत के कुछ वार्डों में कार्य हो रहा हैं तथा बाकी वार्डों में कार्य कोई कार्य नही हो रहा है।उन्होंने अध्यक्ष पर अन्य वार्डो के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। सभासदों ने यह भी कहा कि जब हम सभी लोग किसी कार्य को कराने के लिए कहते हैं तो उसको नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। सभासदों ने यह भी कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा खुले आम मनमानी जमकर किया जाता है। और नगर पंचायत में कराए जा रहे तमाम विकास कार्यों में खुलेआम भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार भी व्याप्त है।भ्रष्टाचार का विरोध जब हम सभी सभासद करते हैं तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। सभासद सुनील विश्वकर्मा, आकाश सिंह अरविन्द प्रजापति, आलोक मौर्य,इकबाल अन्सारी, अखिलेश यादव,इजलाश यादव,सुरज कन्नौजिया,आदि रहे।

भीड़ में घुसी बेकाबू कार, पांच श्रद्धालु घायल

जौनपुर।जलालपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध त्रिलोचन महादेव मंदिर के समीप सोमवार को एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं की भीड़ में जा घुसी। हादसे के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक कार चालक का नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोग तुरंत घायलों की मदद में जुट गए।सूचना मिलते ही जलालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायल अरविंद राजभर को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है।घायलों में अरविंद राजभर (32) निवासी कोड़री, प्रमोद कुमार (32) निवासी गढ़ कोड़री, विशाल मिश्रा (26) निवासी बराई, आयुष सिंह (21) तथा अंजली पटेल (14) निवासी फूलपुर वाराणसी शामिल हैं।पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के चलते कुछ समय तक मंदिर मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर निकाली कलष यात्रा

जौनपुर।सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत जनपद में श्रद्धा, आस्था एवं सांस्कृतिक चेतना से ओत-प्रोत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन., मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी द्वय अजय अंबष्ट, परमानन्द झा सहित अन्य अधिकारीगण की उपस्थिति में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर डाक बंगला चैराहा होते हुए पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर तक पहुँची, जहां पर मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन किया गया तथा लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में अत्यंत उत्साह एवं भक्ति भाव देखने को मिला। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर पारंपरिक एवं धार्मिक वातावरण को और अधिक आकर्षक बनाया। 'हर-हर महादेव' एवं भगवान शिव के जयघोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं एवं आमजनमानस द्वारा पुष्पवर्षा कर स्वागत भी किया गया। कलश यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, छात्र-छात्राएं शिक्षक एवं आमजन उपस्थित रहे। यात्रा के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा एवं धार्मिक एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए थे, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायतों में भी शिव मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा शिवालयों में मंत्रोच्चार, ओंकार जाप, महाआरती रुद्राभिषेक, दीपोत्सव तथा भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ इसमें स्थानीय समुदाय द्वारा जनभागीदारी की गई। साथ ही विभिन्न विद्यालयों में पेंटिंग, रंगोली सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। संचालन शिक्षिका नूपुर श्रीवास्तव द्वारा किया गया। विभिन्न अधिकारीगण, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

हत्या में महिला सहित दो को आजीवन कारावास

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व हत्या कर शव को कुएं में फेंककर साक्ष्य विलोपन के दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के बांसदेवपट्टी गांव निवासी राजेश कुमार पाल ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि सात सितंबर 2018 को दिन में 2रू00 बजे उसके पिता राजेश ट्रैक्टर एजेंसी जाने के लिए घर से निकले थे। देर रात तक वापस घर न पहुंचने पर उनकी खोजबीन की गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उनका मोबाइल नंबर भी बंद था। 10 सितंबर को औरैला गांव स्थित एक कुएं में शव मिलने की सूचना पर वहां जाकर देखा तो कुएं में उसके पिता की मोटरसाइकिल व उनकी लाश मिली, जो 6 टुकड़ों में कटी हुई थी। कुम्हार बस्ती की बिंदु देवी पत्नी मन्नालाल प्रजापति व तीन- चार अन्य लोग मिलकर उसके पिता की हत्या किए हैं। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी बिंदु देवी व नागेंद्र मिश्रा उर्फ लंगड़ा को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।

पोखरे में उतराया मिला वृद्ध की लाष

जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरूद्दीनपुर गांव में सोमवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव के बाहर एक पोखर में वृद्ध का शव उतराया हुआ मिला। मृतक की पहचान 60 वर्षीय मेवा लाल कनौजिया निवासी कबीरूद्दीनपुर के रूप में हुई है, जो रविवार की शाम से ही संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थे। परिजनों के अनुसार, मेवा लाल रविवार शाम को घर से निकले थे, लेकिन जब देर रात तक वापस नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई। रात भर खोजबीन के बाद भी उनका कहीं सुराग नहीं लग सका। सोमवार सुबह पोखर के समीप खेल रहे बच्चों की नजर पानी में तैरते शव पर पड़ी, जिसके बाद बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और परिजनों को घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर तत्काल पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृद्ध की संदिग्ध मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

ट्रैक पर महिला का शव मिलाः कटने का अंदेशा

जौनपुर। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के भलुआही रेलवे क्रॉसिंग के पास सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव मिला। स्थानीय लोगों ने ट्रैक के किनारे क्षत-विक्षत शव देखा और तत्काल इसकी सूचना पुलिस तथा रेलवे अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही बदलापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला की मौत ट्रेन से कटने के कारण हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि, घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर महिला की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। घटना स्थल पर काफी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए थे।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला ट्रेन हादसे का लग रहा है। हालांकि, अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस महिला की शिनाख्त कराने के साथ-साथ यह पता लगाने में जुटी है कि यह घटना दुर्घटना है, आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक फूलचंद पाण्डेय ने बताया कि महिला की शिनाख्त की जा रही है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी।

परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रशासन ने सम सेमेस्टर परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। यह निर्णय प्रतियोगी परीक्षाओं और टीजीटी-पीजीटी परीक्षा में शामिल होने वाले बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध जौनपुर और गाजीपुर जनपद के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा।परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीएससी एजी की सम सेमेस्टर परीक्षाएं अब 18 मई से शुरू होंगी। हालांकि, एलएलबी और एलएलएम की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 मई से ही आयोजित की जाएंगी। विधि पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

घास की रोटी खा ली पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया महाराणा प्रताप नेः डा. महेंद्र सिंह

मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले महान योद्धा को युगों युगों तक लोग करेंगे यादः कृपाशंकर सिंह

कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित प्रेक्षागृह में राजपूत सेवा समिति द्वारा समाज के मेधावियों को किया गया सम्मानित

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित प्रेक्षागृह में शनिवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जयंती पर राजपूत सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित मेधावी प्रतिभा सम्मान का आयोजन हुआ। राजपूत समाज के आईएएस, पीसीएस में चयनित 11 मेधावियों के साथ साथ यूपी बोर्ड में जनपद में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री डा. महेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अदम्य साहस और बीरता के प्रतीक थे। उन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया। वे देश के हर दिल में बसे है। उनके गौरव गाथा को दुनिया में लोग याद कर रहे है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने जिस भारत का सपना देखा था, जिस भारत की वे कल्पना करते थे आज फिर से वो भारत खड़ा हो गया है। दुनियां के अंदर भारत का परचम फहर रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव परिणाम से न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरा देश आह्लादित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व गृहराज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने कहा कि अदम्य साहस और बीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य के प्रयासों के लिए राजपूत समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले इस महान योद्धा को युगों युगों तक याद किया जाएगा। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत किया। सलमान शेख की टीम ने गणेश वंदना के बाद महाराणा प्रताप जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को रोमांचित कर दिया। राजपूत सेवा समिति के सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने स्वागत भाषण के साथ समित के द्वारा समाज हित में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए महाराणा प्रताप पार्क के पास एक संग्रहालय हाल के निर्माण की बात कही। अतिथियों द्वारा पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी अभिषेक सिंह, विशाल सिंह, राजिता सिंह, हिमालय सिंह, आदित्य सिंह, विनीत सिंह, किशन सिंह, प्रमय सिंह के साथ ही यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में जनपद में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र राजशेखर सिंह को सम्मान पत्र व अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। वक्ताओं में पूर्व सांसद डा. कृष्ण प्रताप सिंह, शाहगंज के विधायक रमेश सिंह, पूर्व विधायक डा.हरेंद्र प्रसाद सिंह, समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह, पूर्व चेयरमैन श्रीमती कमला सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, सतीश सिंह, ब्लाक प्रमुख राहुल सिंह, सत्येंद्र सिंह फंटू, विनय सिंह, राहुल सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह मुन्ना, डा. अंजना सिंह सहित समिति के सदस्य व भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। संचालन शरद सिंह व आभार जौनपुर पत्रकार संघ के अध्यक्ष शशि मोहन सिंह क्षेम ने ज्ञापित किया।

बीएसए के औचक निरीक्षण में खुली स्कूलों की हकीकत

कहीं बच्चों संग बैठकर खाया एमडीएम, कहीं गंदगी पर फटकार तो कहीं शिक्षामित्र का मानदेय रोका

जौनपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने शुक्रवार को जिले के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था, छात्र उपस्थिति और मध्याह्न भोजन योजना की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान कई विद्यालयों में लापरवाही सामने आने पर संबंधित प्रधानाध्यापकों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया।बीएसए ने सबसे पहले विकासखंड धर्मापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय शीतला चौकिया का निरीक्षण किया। सुबह 7:50 बजे तक विद्यालय में मात्र 14 छात्र उपस्थित मिले। छात्र उपस्थिति बेहद कम पाए जाने पर प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं अनुपस्थित शिक्षामित्र का मानदेय अगले आदेश तक रोक दिया गया। विद्यालय परिसर और किचन की साफ-सफाई बेहतर मिलने पर रसोइया को प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कृत किया गया।इसके बाद प्राथमिक विद्यालय सिद्दीकपुर, करंजाकला का निरीक्षण किया गया, जहां सभी शिक्षक उपस्थित मिले। विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने पर बीएसए ने सफाई व्यवस्था और बेहतर करने के निर्देश दिए।प्राथमिक विद्यालय खानपुर अकबर में निरीक्षण के दौरान विद्यालय का भौतिक परिवेश बेहद खराब मिला। विद्यालय परिसर में गंदगी, टूटी चहारदीवारी और जल निकासी न होने से जलभराव की समस्या पाई गई, जिससे बच्चों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। इस पर बीएसए ने तत्काल नगर पालिका प्रशासन से वार्ता की। मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता और अध्यक्ष प्रतिनिधि ने एक माह के भीतर विद्यालय परिसर की स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया।वहीं शाहगंज विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय तरसांवा में मध्याह्न भोजन व्यवस्था बेहद अव्यवस्थित मिली। बच्चे बिना किसी शिक्षक की निगरानी के एमडीएम ग्रहण कर रहे थे। इस पर बीएसए ने नाराजगी जताते हुए बच्चों को बरामदे में टाट-पट्टी पर व्यवस्थित बैठाया और स्वयं उनके साथ भोजन किया। एमडीएम की गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापक सहित समस्त स्टाफ का निरीक्षण तिथि का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।कम्पोजिट विद्यालय सिद्दीकपुर, करंजाकला में निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक गुणवत्ता अच्छी पाई गई। कक्षा आठ के छात्र-छात्राओं आरुषि और विशेष ने ब्लैकबोर्ड पर लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक के प्रश्न हल कर अपनी प्रतिभा दिखाई, जिस पर बीएसए ने दोनों विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया।

मानबढ़ ने खड़ंजे को ट्रैक्टर से जोता,रास्ता खत्म करने से गांव में तनाव

जफराबाद।सिरकोनी विकास खण्ड के बदलपुर गांव में एक व्यक्ति ने खड़ंजे को ट्रैक्टर से जोतकर खत्म कर दिया है।जिससे गांव में काफी तनाव व्याप्त है।प्रधान ने पुलिस को प्रार्थनाप देकर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग किया है।उक्त गांव के मुख्य मार्ग से यादव बस्ती जाने के लिए लगभग 350 मीटर खड़ंजा चार दशक पूर्व लगाया गया है।गांव के एक व्यक्ति ने खड़ंजे के बीच मे लगभग 70 मीटर जमीन अपनी बताते हुए ट्रैक्टर से जोत कर खत्म कर दिया।गांव के काफी लोग प्रधान संजय सिंह जलालपुर थाने पर पहुंच गए।उन्होंने गांव के एक पिता पुत्र के विरुद्ध तहरीर दिया। प्रधान संजय सिंह ने बताया कि गांव में लगभग चार दशक पहले से उक्त खड़ंजे को बनाया गया था।उसको क्षतिग्रस्त करने से सैकड़ो लोगों के आने जाने का रास्ता खत्म हो गया है।इस बारे में थानाध्यक्ष प्रशांत सिंह ने बताया कि समाधान दिवस पर ग्राम प्रधान ने उक्त मामले का प्रार्थनापत्र दिया।उनके प्रार्थनापत्र पर नायब तहसीलदार प्रमोद यादव ने उक्त हल्के के कानूनगो को मौके पर राजस्व व पुलिस की टीम को जाकर मुआयना करके रिपोर्ट देने को कहा है।गलत मिलने पर आरोपी पर कार्यवाही होगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 57495 मामलें हुए निस्तारित

जौनपुर। प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व श्री सुशील कुमार शशि, माननीय जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर की अध्यक्षता एवं श्री रणजीत कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/नोडल अधिकारी लोक अदालत, जौनपुर व श्री सुशील कुमार सिंह, सिविल जज सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर की देखरेख में जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में दिनांक 09.05.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गयाइस अवसर पर माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री नीरज तिवारी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व जनपद न्यायाधीश जौनपुर द्वारा माँ सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया तथा उनके द्वारा अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु सर्व सम्बन्धित को प्रोत्साहित किया गयाइस अवसर पर श्री सैमुअल पाल एन0, जिलाधिकारी, जौनपुर, श्री कुवर अनुपम सिंह, पुलिस अधीक्षक, जौनपुर, श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव ।।, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 श्री मनोज कुमार अग्रवाल, समस्त अपर जनपद न्यायाधीशगण तथा समस्त सिविल व फौजदारी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहेराष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित 6591 एवं राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में प्रीलिटिगेशन वाद के कुल 50904 मामलें निस्तारित हुए तथा समझौता राशि कुल रू0 128905563 रुपये की गइपारिवारिक न्यायालयो द्वारा 55 मुकदमों को निस्तारित किया गया जिसमें पीड़िता को मु0 3781000 रूपये की समझौता राशि प्रदान करायी गयीइस अवसर पर पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0 द्वारा क्षतिपूर्ति के 42 मुकदमें लगाये गये जिनमें से 29 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल रू0 33430000 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति याचीगण को दिलायी गयीन्यायालय अपर जिला जज चतुर्थ जौनपुर द्वारा विद्युत वसूली के 563 वादों का निस्तारण किया गयाविभिन्न न्यायालयों द्वारा 5193 शमनीय फौजदारी वादों को निस्तारित किया गया जिनमें रू0 367680 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। एन0 आई0 एक्ट के 02 मामलों का निस्तारण किया गया तथा अन्य प्रकार के 686 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें समझौता राशि रू0 346547 दिलाया गयासिविल न्यायालयों द्वारा कुल 64 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में मु0 6054034 रूपये का प्रमाण पत्र निर्गत किया गयाप्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवाद के 01 मामलों का निस्तारण किया गया तथा राजस्व न्यायालयों फौजदारी के 2087 वादों, राजस्व के 715 वाद एवं अन्य प्रकार के 47207 व नगर पालिका द्वारा जलकर से सम्बन्धित 110 वादों का निस्तारण किया गयाबैंक/फाइनेंस कम्पनी एवं बी0एस0एन0एल0 आदि के रिकवरी से सम्बन्धित 784 प्री-लिटिगेशन वाद निस्तारित किये गये तथा जिसमें मु0 82883190 रुपये का समझौता किया गयाइस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 57495 मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें कुल रू0 128905563 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गयाइस दौरान लोक अदालत के अवसर पर विभिन्न श्रम कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र श्रमिकों एवं उनके परिजनों को हितलाभ/ चेक, दिव्यांग विभाग अंतर्गत उपकरण वितरण तथा उद्योग विभाग अंतर्गत उपकरण किए गए वितरितइस अवसर पर मातृत्व, शिशु एवं बालिका हित लाभ योजना, कन्या विवाह सहायता योजना तथा मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 05 लाभार्थियों को रु. 5,34,982 की सहायता राशि प्रदान की गइमातृत्व, शिशु एवं बालिका हित लाभ योजना के अंतर्गत दो लाभार्थियों क्रमशः नेहा निवासी सिरकोनी को रु0 83,982 एवं घनश्याम निवासी सिरकोनी को रु0 56,000 की सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत दो लाभार्थियों निर्मला निवासी जलालपुर और दुर्गावती निवासी शाहगंज को रु. 85,000-रु. 85,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

एक साल से चोक थी सीवर लाइन, परेशान महिला जान देने तीसरी मंजिल पर चढ़

कानपुर। चकेरी के अहिरवां में एक साल से सीवर चोक होने से परेशान महिला ने शुक्रवार को घर की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। पुलिस के हस्तक्षेप और मामला तूल पकड़ने के बाद जलकल विभाग ने आनन-फानन में रात से ही सफाई कार्य शुरू कर दिया है।कानपुर में चकेरी के अहिरवां विराटनगर में एक साल से सीवर लाइन चोक होने से परेशान होकर महिला शुक्रवार को जान देने के लिए घर की तीसरी मंजिल पर चढ़ गई। हंगामा करने के साथ ही महिला ने छत से कूदने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर नीचे उतार लिया।

विपक्ष की क्या मजबूरी, महिला आरक्षण से क्यों दूरी

जौनपुर। भाजपा की महिला जन आक्रोश के तहत धरना प्रदर्शन में बोलते हुए जिला मंत्री अंशु कुशवाहा ने कहा कि नारी शक्ति ने हमेशा देश को दिशा दी है, लेकिन जब बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे हक की आती है, तो देरी क्यों? संसद में हमारी भागीदारी हमारा अधिकार है, कोई खैरात नहीं आज की ये खामोश गूँज कल के बदलाव की आहट है जब तक अधिकार नहीं तब तक धरना के माध्यम से उनका विरोध करते रहेंगे घर चलाने वाली नारी अब देश की नीतियां भी तय करेगी नारी वंदन अधिनियम के पास होने में हो रही देरी सिर्फ एक कानून की देरी नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं के सपनों की देरी है सड़कों पर उतरी ये महिलाएं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा रागिनी सिंह ने कहा कि यह बिल देश की उस सरकार की इच्छाशक्ति का परिणाम है आज हम यहाँ एक बहुत ही गंभीर विषय पर इस धरना-प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज उठाने आए हैं दशकों से भारतीय राजनीति में हमारी माताओं-बहनों को उनका हक देने की बातें तो होती थीं, लेकिन नियत साफ नहीं थी। लेकिन बहनों, अफसोस की बात देखिए! जो विपक्ष खुद को जनता का हितैषी बताता है, उसी विपक्ष ने इस बिल की राह में रोड़े अटकाने का काम किया। जब संसद में माँ भारती की बेटियों को उनका अधिकार दिया जा रहा था, तब विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे थे, कमियाँ निकाल रहे थे और इसे रोकने की साजिश रचे। जिला उपाध्यक्ष राखी सिंह ने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ उन विपक्षी दलों से क्या इस देश की बेटी नीति-निर्धारण में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है? क्या आपको डर है कि अगर महिलाएँ सदन में पहुँच गईं, तो आपकी परिवारवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी विपक्ष का यह विरोध केवल एक बिल का विरोध नहीं है, बल्कि यह देश की आधी आबादी के सपनों का विरोध है। यह उस हर उस महिला का अपमान है जो समाज में बराबरी का हक चाहती है। इन्होंने सालों तक इस बिल को फाइलों में दबाए रखा और आज जब यह हकीकत बना है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अंजना सिंह ने कहा कि बहनों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है जो लोग आज सड़कों पर आकर झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, संसद में उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है । मोनिका सिंह शशि मौर्य विमला श्रीवास्तव किरन मिश्रा प्रीति गुप्ता सारिका सोनी वंदना सिंह मिलन श्रीवास्तव सहित सैकड़ों महिला उपस्थित रहीं।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न

जौनपुर । जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में शुक्रवार देर सायं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्षवार निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुनिश्चित करें कि अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ न मिले। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मनरेगा योजना की भी समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की कि मनरेगा के अंतर्गत कितने मानव दिवस (मैन डेज़) सृजित किए जा रहे हैं तथा श्रमिकों को समय से भुगतान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा कार्यों में तेजी लाई जाए तथा विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। जिलाधिकारी द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि अभी से गड्ढा खुदान एवं पौध तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए तथा नर्सरियों का निरीक्षण कर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में व्यापक स्तर पर पौधरोपण की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए खंड विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त पैच चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही समय से पूर्ण करें।इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा फॉर्मर रजिस्ट्री की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सबसे कम प्रगति वाले विकास खंडों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि फॉर्मर रजिस्ट्री का कार्य शासन की प्राथमिकता में है, अतः सभी अधिकारी लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों से कहा है कि लाभार्थीपरक योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक पहुँचने चाहिएकृषि विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि पीएम कुसुम योजना का इस जनपद में अधिक स्कोप है, इससे अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाए। एआर कोऑपरेटिव से खाद की उपलब्धता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की।

स्वदेश भारत न्यूज
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र
स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक स्वदीश कुमार द्वारा स्वदेश भारत पब्लिकेशन ग्राम कनकपुर पोस्ट फतेहगंज जिला जौनपुर (उ०प्र०) 222132 से मुद्रित एंव प्रकाशित ।
सम्पादक
स्वदीश कुमार
मो0 9628825379
संरक्षक संजय गुप्ता
7860079888
उप संरक्षक- आदित्य मौर्या
प्रधान संम्पादक- राकेश मौर्या
उप संम्पादक – नियामअतुल्ला
समाचार संम्पादक- विनय कुमार
सह संपादक- तबरेज नियाजी
कार्यकारी सम्पादक
राजेश गौतम, सतीश चौहान
प्रबन्ध संम्पादक –रंजीत कुमार
@-swadeshbharatnews@gmail-com
समस्त वादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा